12th March, 1981, regarding setting up of the Commission for Additional Sources of Energy [*Placed in Library See* No. LT-2077/81]

(2) A copy of Govenment Resolution No. F.20019/1/81-ADM-1 dated the 12th March, 1981 regarding setting up of the Science Advisory Committee to the Cabinet [*Placed in Library See* No. LT 2078/81]

18.04 hrs.

GENERAL BUDGET, 1981—82
GENERAL DISCUSSION—*contd.*

श्रीमती ऊषा वर्मा (खेरी) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने जो बजट नए वर्ष के लिए पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं । मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि इससे अच्छा बजट वर्तमान स्थिति में बनाना संभव नहीं था जब कि जनता पार्टी और लोकदल की सरकारों ने तीन वर्षों में देश की अर्थ-व्यवस्था को बुरी तरह बिगाड़ दिया है । मैं यह कहना चाहती हूं कि एक लंबे अरसे के बाद गरीब और मध्यम श्रेणी की जनता को राहत पहुंचाने के लिए ठोस उपाय किए गए हैं । इसके साथ ही टैक्सों का नया बोझ नहीं लादा गया है, बल्कि विकास और उत्पादन को बढ़ावा देने का रास्ता खोला गया है । छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए गए हैं, किंतु मेरा आग्रह है कि कृषि और गांवों के विकास की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए । इस कार्य के लिए और अधिक प्रावधान करने का मैं वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध करती हूं । 16 फरवरी को ऐतिहासिक किसान रेली ने यह साबित कर दिया है कि देश का किसान हमारी महान नेता श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ है । देश का किसान और अधिक राहत की आशा करता है ।

मैं सरकार का ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहती हूं कि पिछड़े हुए ग्रामीन इलाकों में तथा आदिवासी जंगली क्षेत्रों में भूमिहीन खेतीहर मजदूरों की हालत अच्छी नहीं है और रोजगार नहीं मिलने के कारण वे शहरों की ओर भाग रहे हैं । इन खेतीहर मजदूरों को खेती के लिए जमीन दी जाए । कृषि पर आधारित ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए योजना में और अधिक प्रावधान करना जरूरी है ।

मेरे क्षेत्र लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश का चालीस फीसदी जूट पैदा होता है । पिछले दो वर्षों से मेरे जिले के किसानों से भारतीय पटसन निगम जूट नहीं खरीद रहा है । इस कारण दस हजार टन से अधिक जूट किसानों के पास पड़ा हुआ है और उनका पैसा फंस गया है । वहां जूट का भाव अन्य स्थानों से बीस रुपया प्रति क्विंटल ज्यादा रखा गया है । मैं चाहती हूं कि सभी स्थानों पर दरें एक समान होनी चाहिएं ताकि जूट मिलें जूट को खरीद सकें । साथ ही सरकार लखीमपुर खीरी जिले से जूट खरीदने का प्रबन्ध भी करे ।

स्वयं अपना व्यवसाय या उद्योग चलाने की इच्छा रखने वालों को बैंकों से आसान शर्तों पर ऋण की सहायता मिलनी चाहिए । बैंक इस बारे में अच्छा रवैया अख्तियार नहीं करते । कृषि ऋण भी लक्ष्य के अनुसार नहीं बांटा जा रहा है । सरकारी वित्त निगमों को भी स्वयं व्यवसाय करने वालों की मदद के लिए आगे आना चाहिए ।

समाज के छोटे तबकों में आत्मनिर्भरता पैदा करने के लिए सभी किस्म की सहकारी समितियों को हर प्रकार का उद्योग व्यवसाय चलाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए । विशेष कर मजदूर

[श्रीमति ऊषा वर्मा]

वर्ग में सहकारिता आन्दोलन का विकास किया जाना चाहिए ।

मैं विरोधी पक्ष के सभी सम्मानित सदस्यों से अनुरोध करूंगी कि वे नए बजट को राजनीतिक दृष्टिकोण से न देखें। देश के विकास के लिए सभी को मिल-जुल कर कोशिश करनी चाहिए। नया बजट अमीरों का नहीं, गरीबों का बजट है। उसकी अच्छाइयों को देखा जाना चाहिए। वित्त मंत्री जी के बजट प्रस्तावों का पूरा पूरा समर्थन किया जाना चाहिए। कुछ लोग मुद्रा के फैलाव और महंगाई की बात करते हैं। किन्तु उत्पादन को घटाने वाले आन्दोलन करते हैं। हमारी प्रधान मंत्री जी ने समाज के सभी वर्गों से आर्थिक विकास में सहयोग करने की अपील की है। विरोध पक्ष से मैं प्रधान मंत्री जी के आह्वान का उत्तर देने की अपील करती हूं और अपने वित्त मंत्री जी से आगे भी इस किस्म के और किसानों को राहत पहुंचाने वाले बजट पेश करने का आग्रह करती हूं ।

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : इस बजट का गहराई से अध्ययन किया जाए और सत्ता पक्ष की बातों को देखा जाए, बजट के ऊपर जो समाजवादी बुरका लगा हुआ है यदि इस बुरके को हटा दिया जाए तो बुरके के अन्दर मात्र वस्त्रहीन पूंजीवादी बजट है जो इजारेदारों, पूंजीपतियों, विदेशी कम्पनियों और विश्व बैंक के दबाव में आकार बनाया गया है। इस बजट में 20 प्रतिशत का प्रावधान तो पब्लिक सैक्टर के लिए किया गया है और 80 प्रतिशत का प्रावधान प्राइवेट सैक्टर के लिए किया गया है, उनको बड़ी बड़ी रियायतें पहले ही दी गई हैं। श्री एल० के० झा को आर्थिक सुधार आयोग का चेयरमैन बना दिया गया है जो अपने आप में इस बात का सबूत है कि यह बजट इजारेदारों के दबावों में आकर बनाया गया है ।

बजट में हरिजनों के उद्धार की बात कही गई है और बड़े दावे के साथ कही गई है कि यह हरिजन-आदिवासियों के बड़े काम का बजट है। जब कि गुजरात में हरिजन मारे जा रहे हैं। वहां पर सरकार उन की रक्षा नहीं कर पा रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस बजट में हरिजनों की मद में जो पैसा दिखाया गया है क्या वह पैसा हरिजनों के लिए बेहतरीन कबरिस्तान बनाने के लिए रखा गया है? कर्नाटक में बेलगांव, बीजापुर, गुलबर्गा और धारवार तथा महाराष्ट्र में शोलापुर, कोल्हापुर और सांगली आदि जैसे ऐसे स्थान हैं, जहां प्रति वर्ष पांच हजार से छः हजार हरिजन आदिवासी लड़कियों को एलम्मा देवी के मन्दिर में देवदासी बनाया जाता है। पुजारीगण मन्दिर में उन के साथ बलात्कार करते हैं फिर उन्हें बड़े बड़े वेश्यालयों में बेचा जाता है, जो सरकार हरिजन-आदिवासी बहू-बेटियों की रक्षा नहीं कर सकती है, वह उन्हें रोटी कैसे देगी, यह सोचना पड़ेगा ?

वित्त उप-मंत्री, श्री वरोट, यहां बैठे हैं। मैं उन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उन का मंत्रालय शिड्यूल्ड कास्टस के प्रति कितना हमदर्द है। स्टेट बैंक आफ इंडिया में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती के लिए एक मैरिट-लिस्ट बनी थी। मंत्री महोदय ने 13 जून, 1980 को प्रश्न संख्या 789 के उत्तर में इस सदन को यह आश्वासन दिया था कि जब तक शिड्यूल्ड कास्टस का कोटा पूरा नहीं होगा, तब तक इस लिस्ट को बरकरार रखा जायेगा। लेकिन उन के इस आश्वासन के पन्द्रह दिनों के अन्दर ही उस लिस्ट के गैर-शिड्यूल्ड कास्टस के सब लोगों को ले लिया गया और उस के बाद वह लिस्ट कैंसल कर दी गई। मंत्री महोदय ने यह आश्वासान दिया था कि यह लिस्ट

एक साल तक एडजस्ट करेगी। मैं और मेरे मित्र, श्री जयपाल सिंह कश्यप, मंत्री जी से मिले थे, तो उन्होंने लिखित जवाब दिया था कि हम इस को देख रहे हैं। उन्हों ने 27 नवम्बर, 1980 को बताया कि हम उसे देख रहे हैं। तब से वह उसे देख रहे हैं। इस से पता लगता है कि शिडयूल्ड कास्ट्स के प्रति वह कितने हमदर्द हैं।

जहां तक इस देश के पूंजीपतियों का सम्बन्ध है, 1947 में बिड़ला की परिसम्पत्ति 589.42 करोड़ रुपये थी, जो बढ़ कर 1978 में 1171 करोड़ रुपये हो गई। इसी अवधि में टाटा की परिसम्पत्ति 641.93 करोड़ रुपये से बढ़ कर 1102.11 करोड़ रुपये हो गई। इसी तरह अन्य इजारेदारों की परिसम्पत्ति भी बढ़ी है, जबकि गरीब और गरीब हुए हैं।

यदि इस देश की सोसायटी के आर्थिक ढांचे का विश्लेषण किया जाये, तो पता लगता है कि इस देश में एक लाख रुपए से ऊपर की हैसियत के लोग 1 परसेंट, एक लाख रुपए से 50,000 रुपए तक की हैसियत के लोग 4 परसेंट और 50,000 रुपए से 10,000 रुपए तक की हैसियत के लोग 5 परसेंट हैं। इन्हीं दस परसेंट लोगों ने देश की आजादी को भोगा है।

10,000 रुपये से 5,000 रुपए तक की हैसियत के लोग 10 परसेंट हैं और गरीबी की रेखा के ऊपर के लोग 30 परसेंट हैं। ये 40 परसेंट मध्यम वर्ग के लोग हैं। सरकार की ओर से कहा जाता है कि आयकर की छूट को 12,000 रुपए से बढ़ा कर 15,000 रुपए तक कर देने से मध्यम वर्ग को फायदा हुआ है। इस बजट की घोषणा से चौबीस घंटे पहले 12,000 रुपए की कीमत 18,000 रुपए थी और उस के चौबीस घंटे के अन्दर वह 20,000 रुपए हो गई। सरकार ने 15,000 रुपए तक की छूट दी है। तो मध्यम वर्ग को उस को एडजस्ट करने के लिए 5,000 रुपये कहां से मिलेंगे ? वास्तव में सरकार ने कोई छूट नहीं दी है, बल्कि उस ने वह बजट इस सफाई से रखा है कि मध्यम वर्ग उस को समझ न पाये।

मंत्री महोदय ने कहा है कि इस बजट के द्वारा 30 लाख लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया जायेगा। इस देश में 50 प्रतिशत लोग, अर्थात 35 करोड़ लोग, गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। इस का मतलब यह है कि सरकार को केवल 30 लाख लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना है, तो 34.70 करोड़ लोगों के लिये इस बजट का कोई सम्बन्ध नहीं है। क्या उन के लिए कोई दूसरी सरकार और कोई दूसरा बजट आएगा ? 25 प्रतिशत लोग अर्थात साढ़े सत्तरह करोड़ लोग ऐसे हैं जो आधा पेट खाना पाते हैं। उन का इस बजट से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस देश में 12 प्रतिशत अर्थात 8 करोड़ लोग ऐसे हैं जो साल में केवल तीन महीने खाना खाते हैं और नौ महीने तक सांप, छछूंदर, बिच्छू, गोजर गीदड़-गिलहरी आदि खा कर गुजारा करते हैं। बिहार के अनेक स्थानों में तथा उत्तर प्रदेश के इलाहबाद जिले की मझंरपुर तहसील में ऐसे कई गांव हैं जहां लोग दो दो, तीन तीन महीने पेड़ के पत्ते और घास वगैरह खा कर अपना जीवन बिताते हैं, हाय! यह बजट इन के लिए भी गूंगा, बहरा और अंधा है।

बजट में शिक्षा पर बड़ा जोर दिया गया है। जब प्रधान मंत्रीजी कहती हैं कि शिक्षा दोषपूर्ण है तो इस शिक्षा पर इतना क्यों खर्च किया जा रहा है ? क्या इसलिए कि शिक्षा के निर्गुण रूप को तो सरकार जानती है, लेकिन सगुण रूप को नहीं जानती है ?

इसी बजट में बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि अखबार वालों पर 15 प्रतिशत लैवी लगा दी गई है। अखबार एक जन-साधारण की चीज थी, अखबार के माध्यम से

[श्री आर० एन० राकेश]

हम यह जान सकते थे कि देश किस दिशा में जा रहा है। यह गरीब देश है, हर आदमी के पास यहां रेडियो और ट्रांजिस्टर नहीं है। अखबार से ही उस को कुछ समाचार मिल पाता है। लेकिन उस पर भी आप ने लैवी इसलिए लगा दी कि उन को आप अपनी धौंस में ला सकें और अपने मन की करा सकें। इस लैवी से वे लोग जो सरकार के पक्ष में हैं, जो सरकार की धौंस में आ चुके हैं वे प्रभावित नहीं होंगे, उन के ऊपर इस लैवी का कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो गरीब अखबार वाले हैं जो सरकार की धौंस में नहीं आ पाये हैं, उन के ऊपर यह लैवी मौत-मार होगी। दूसरी ओर जो सरकार के पक्ष के अखबार हैं उन को सरकारी विज्ञापन मिलेंगे, और तरीकों से भी उन को बढ़ावा मिलेगा। मैं चाहता हूं कि अखबार वालों को तो कम से कम इस लैवी से मुक्त किया जाय। बार बार अखबार की स्वतन्त्रता की बात की जाती है। मैं कहता हूं कि अखबार अपने आप स्वतन्त्र रहेंगे, लेकिन सरकार उन के ऊपर से अपने नापाक साये को हटा दे।

इस देश में बेरोजगारी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। उस को समाप्त करने के लिये इस बजट में कोई चर्चा नहीं की गई है। 90 मिलियन जाब दस साल में क्रिएट होने चाहिए थे, अर्थात प्रति वर्ष 9 मिलियन जाब तैयार होने चाहिए थे। लेकिन पिछली पंचवर्षीय योजना में चार मिलियन जाब ही तैयार किया गया और इस बजट में तो बेरोजगारी को समाप्त करने के लिये कोई चर्चा ही नहीं की गई है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं इस दिशा में कि बजट में फिर से सुधार किया जाय जिस से कि इस देश की बेरोजगारी को दूर किया जा सके। आज दसियों करोड़ लोग इस देश में बेरोजगार हैं। दूसरे देशों में वर्किंग अवर्स कम किए गए हैं। आप भी वर्किंग अवर्स कम करिए और बाकी समय में और लोगों को रोटी-रोजी देने के लिए सोचिए।

काले धन के बारे में बड़ी चर्चा की गई है कि यह सरकार का बड़ा पुनीत काम है। इस सरकार ने काले धन को सफेद करने का जरूर बड़ा पुनीत कार्य शुरू किया है। परन्तु यह सरकार जो काले धन की औलाद है क्या वल्दियत बदल कर विश्वसनीयता प्राप्त कर सकेगी? इन शब्दों के साथ मैं बजट का विरोध करता हूं।

श्री लक्ष्मण कर्मा (बस्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1981–82 का जो बजट प्रस्तुत है उस का मैं समर्थन करता हूं। यह बजट जन-सामान्य के लिए राहत का बजट है। इस देश में पहली बार कृषि विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक की स्थापना करने और देहाती क्षेत्रों के लिये क्षेत्रीय विकास बैंकों की स्थापना करने तथा जीवन बीमा निगम के नियमों में परिवर्तन करने की जो बात कही गई है उस को देखते हुए ऐसा लगता है कि यह समाजवादी बजट है और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए यह एक अच्छा कदम है। हमारे वित्त मंत्री जी ने ग्रामीण विद्युतीकरण का जो कार्यक्रम दिया है उस से देहाती क्षेत्रों में काफी विद्युतीकरण हो सकेगा और कमजोर वर्गों को उस से लाभ होगा। कमजोर वर्गों के लिए और हरिजनों और आदिवासियों के लिए इस में बहुत काफी ध्यान दिया गया है। 10 करोड़ की जो योजना हरिजनों के लिए और 175 करोड़ का जो प्रावधान आदिवासियों के लिए रखा गया है इस से उन को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का मौका मिलेगा। लेकिन उन को और विशेष सुविधा देने की आवश्यकता है। रिजर्वेशन देने के बाद भी हरिजन/आदिवासी आज बहुत अधिक पिछड़े हुए हैं। उन को ऊपर उठाने के लिए विशेष प्रावधान करने की आवश्यकता है। हरिजन आदिवासियों के बच्चों की पढ़ाई के लिए जो सुविधा प्रदान की जा रही है उस में और अधिक वृद्धि

की जानी चाहिए । हरिजन आदिवासियों के बच्चों की पढ़ाई के लिए जब स्कूलों में अच्छी व्यवस्था होगी तभी वे पढ़ सकेंगे और नौकरियों के अवसर भी प्राप्त कर सकेंगे। आज हरिजन आदिवासियों के बच्चे नौकरी के लिए इंटरव्यू में जाते हैं फिर भी जो उन का रिजर्वेशन का कोटा है वह पूरा नहीं हो रहा है। इस का कारण यह है कि वे देहातों में पढ़ाई कर के शहर के बच्चों के साथ आई० ए० एस० तथा अन्य सेवाओं में कांपीटीशन में मुकाबला नहीं कर पाते हैं। मेरा सुझाव है कि उनके लिए अलग से कोचिंग क्लासेज की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि वे भी दूसरों के साथ बराबरी में आ सकें। आज गांवों में शिक्षा का मीडियम हिन्दी है जब कि शहरों में अंग्रेजी है। यही कारण है कि कांपीटीशन में शहरों के बच्चे आ जाते हैं और गांवों में हरिजन आदिवासियों के बच्चे चूंकि हिन्दी में शिक्षा ग्रहण करते हैं, वे उन का मुकाबला नहीं कर पाते हैं। इसलिए देहातों में भी इंगलिश माध्यम की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए जहां पर अनिवार्य रूप से हरिजन आदिवासीयों के बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। तभी कांपीटीशन में वे दूसरों की बराबरी करने में समर्थ हो सकेंगे ।

इस बजट के द्वारा पहली बार गरीब मध्यम वर्ग को राहत देने की योजना बनाई गई है। 12 हजार से बढ़ा कर 15 हजार तक की आमदनी को आयकर से छूट दी गई है। इस के द्वारा लाखों लोगों को राहत मिल सकेगी। इस प्रकार साधारण लोगों को पहली बार इस बजट के द्वारा राहत दी जा रही है।

मैं कुछ मध्य प्रदेश के बारे में भी बतलाना चाहता हूं। मध्य प्रदेश इस देश का हार्ट है। अगर हार्ट ही कमजोर होगा तो शरीर किस प्रकार से मजबूत हो सकेगा। मध्य प्रदेश में हरिजन आदिवासी अधिक संख्या में रहते हैं। वहां बस्तर का क्षेत्र एक आदिवासी जिला है जो कि सब से पिछड़ा हुआ है। वहां पर 80 प्रतिशत से अधिक आदिवासी रहते हैं। वहां पर लोहे और मैंगनीज की खदानें हैं। वन सम्पदा भी वहां पर प्रचुर मात्रा में है। परन्तु वहां की खनिज सम्पदा का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। वहां पर जब तक वन एवं खनिज सम्पदा पर आधारित उद्योग नहीं खोले जायेंगे तब तक वहां के लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हों सकेंगे और न ही वे ऊपर उठने में समर्थ हो सकेंगे। मध्य प्रदेश में ऐसे 17 जिले हैं जिन का विकास बहुत कम होता है। वहां पर आवागमन के साधन बहुत कम हैं। शिक्षा के क्षेत्रों में जो कालेज वगैरह हैं वह शहरी क्षेत्रों में ही हैं, देहातों में नहीं हैं। इस के कारण गांव के बच्चों को शहरों में जा कर शिक्षा ग्रहण करने में बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए देहातों में भी कालेज खोले जाने चाहिएं जिस से कि देहाती बच्चों को भी शिक्षा का लाभ मिल सके।

मध्य प्रदेश में आदिवासियों का शोषण अधिक होता है। इसका कारण यह है कि वहां पर ठेकेदारी प्रथा प्रचलित है। शराब के ठेकेदारों द्वारा आदिवासियों का अधिकतर शोषण होता है। इसलिए इस ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए, इस काम को पब्लिक सैक्टर में किया जाना चाहिए और कानून बना कर उन पर कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए। हरिजन आदिवासियों के लिए सरकार जो कर रही है और रिजर्वेशन दे कर जो सुविधा बढ़ाई है वह प्रशंसनीय है। इन्दिरा जी ने हरिजन आदिवासियों की ओर विशेष ध्यान देकर उन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है। बस्तर जिला आवागमन की सुविधाओं से बहुत पिछड़ा हुआ है। वहां पर 1971–72 में एक रेलवे लाइन का सर्वे हुआ था—दिल्ली-राजस्थान से जगदलपुर को जोड़ने के लिए—जो कि 234 किलोमीटर की लाइन है, उस को पूरा करने के लिए रेलवे बजट में शामिल करना चाहिए, लेकिन रेल मंत्री महोदय ने इस पर कोई ध्यान नहीं

[श्री लक्ष्मण कर्मा]

दिया है । इस को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश के बजट में व्यवस्था बहुत कम है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वहां के लोगों को सुविधा हो सके और उद्योग खुल सकें ; इसलिए इस लाइन को भी लेना चाहिए था ।

वहां पर उद्योग न खुलने का एक कारण यह है कि वहां पर रेलवे की सुविधा और आवागमन की सुविधा नहीं है । इसलिए वहां पर वन-सम्पदा होते हुए भी लोग वहां पर उद्योग लगाने के लिए नहीं जाते हैं। मध्य प्रदेश के पिछड़ा होने का एक कारण यह है कि वहां की आदिवासी जनता की आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से शिक्षित नहीं है । इन सब को देखते हुए, जो केन्द्रीय सहायता मध्य प्रदेश सरकार को दी जाती है, उसको भी बढ़ाना चाहिए ।

बस्तर जिला तीन राज्यों की सीमा रेखाओं से मिला हुआ है—आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा—इस के साथ एक समस्या यह भी है कि नक्सलवादी लोग वहां पर घुस गए हैं, जो कि आदिवासियों के जनजीवन की लूटमार करते हैं । इसको सुरक्षा के लिए भी शासन को विशेष ध्यान देना चाहिए । सीमा रेखाओं पर विशेष पुलिस फोर्स रखनी चाहिए और उन की देख-रेख के लिए कड़े कानून बनाने चाहिएं, तभी वहां के हरिजन आदिवासीयों की सुरक्षा हो सकती है ।

बस्तर जिले में वन सम्पदा बहुत है । वहां जंगल हैं, लेकिन उन को काट कर वहांकी सरकार ने पाइन लगाने की योजना बनाई है। साल के जंगलको काटकर पाइन लगानें की योजना बहुत ही हानिकारक है, जिसकी वजह से वहां का जनजीवन भयभीत है—मैं चाहता हूं कि इस योजना को समाप्त करना चाहिए । वहां के लोगों का जीवन वहां की वन-सम्पदा पर आधारित है, जंगलों से वहां सुविधायें प्राप्त होती है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यदि आदिवासियों को बचाना है, तो जंगलों को बचाना पड़ेगा । नए जंगल लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो पुराने जंगल हैं, उन को प्रीजर्व करने की जरूरत है । इसलिए मैं कहता हूं मध्य प्रदेश शासन ने जो जंगल काटने की योजना बनाई है, उस को खत्म कर देना चाहिए और जो पुराने जंगल हैं, उन को बचा कर रखना चाहिए ।

इन शब्दों के साथ मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आप ने बजट पर बोलने के लिए समय दिया ।

श्री जय राम वर्मा (फैजाबाद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में खड़ा हुआ हूं । जनवरी, 1980 में जब इस सरकार ने कार्यभार संभाला था, उस वक्त सकल राष्ट्रीय उत्पादन में 4.5 प्रतिशत की गिरावट आ गई थी और मूल्यों में 21 प्रतिशत की वृद्धि हो गई थी । आधारभूत ढांचे की उपेक्षा और दुर्व्यवस्था के कारण विद्युत्, कोयला और रेल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संकट की स्थिति पैदा हो गई थी । ऐसी बिगड़ती हुई स्थिति को और आगे बिगड़ने से रोकने में अर्थव्यवस्था में एक ब ार पुनः सुधार और सुस्थिरता लाने में हमारे वित्त मंत्री जी ने श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जो सफलता प्राप्त की है, उस के लिए वह बधाई के पात्र हैं ।

श्रीमान्, ऐसी खराब हालत में केवल 271 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर लगाकर और विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न राहतें प्रदान कर के, जैसे मध्यम वर्ग आय कर दाताओं के 25 लाख लोगों को कर में छूट दी गई है और दूसरे और क्षेत्रों में सुधार के उपाय किए गए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के क्षेत्र में हरिजन और जनजाति तथा कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए, सुधार के लिए, धन की व्यवस्था की गई है, उद्योगों को राहत पहुंचाने की व्यवस्था की गई है, इन सब के करते हुए भी माननीय वित्त मंत्री जी

ने केवल 1539 करोड़ रुपये के घाटे का बजट जब कि वर्तमान हालत को देखते हुए इस वर्ष बहुत बड़े घाटे की आशंका थी, बहुत कर लगाये जाने की आशंका थी, जिस कुशलता और विश्वास के साथ पेश किया, उस के लिए वे हमारी भूरि-भूरि प्रशंसा के पात्र हैं ।

सन् 1980-81 वर्ष में कृषि के क्षेत्र में अच्छे कार्य निष्पादन की वजह से जो अच्छे काम हुए उन के कारण सन् 1980-81 में कृषि का रिकार्ड उत्पादन हुआ, जो 1320 करोड़ टन होने जा रहा है । यद्यपि उद्योगों में उतना सुधार नहीं हुआ है, लेकिन उन में भी अब सुधार चल पड़ा है। और यह आशा है कि 1981-82 में सकल राष्ट्रीय-उत्पाद में साढ़े छः प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी । हमारा भारत गांवों में रहता है, जहां 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि के ऊपर अपनी आजीविका के लिये आधारित है । इसलिये देश की खुशहाली कृषि के विकास और उस के आधुनिकीकरण पर निर्भर करती है । इसलिए यह कहा जा सकता है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था में कृषि की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, कृषि के उत्पादन की दर समूची राज-व्यवस्था की दर को निर्धारित करती है । इस दृष्टि से कृषि ही हमारे देश की समृद्धि का कारण बन सकती है । इस बजट में कृषि के शोध के लिये, उस की उन्नति के लिये, विशेष रूप से व्यवस्था की गई है । इस वर्ष की योजना में 1047 करोड़ रुपये का प्रावधान पिछले वर्ष के 925 करोड़ रुपये के स्थान पर रखा गया है तथा यह व्यवस्था भी की गई है कि 1981-82 में 25 लाख हैक्टेयर जमीन को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा प्रदान की जायगी तथा गांवों के विद्युतीकरण के कामों को आगे बढ़ाया जायगा । ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत इस वर्ष 22 हजार गांवों को शामिल किया गया है तथा साढ़े चार लाख पम्प-सैटों को विद्युत देने की व्यवस्था की गई है । जिन गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, उन में पीने के पानी की व्यवस्था की जायगी, ऐसे 36 हजार गांवों में ऐसी व्यवस्था हो जायगी । हमारे वित्त मंत्री जी ने इस बात की भी घोषणा की है कि एक राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की जायगी जिसके द्वारा शीर्ष स्तर पर गांवों के लोगों की ऋण सम्बन्धी जरूरतों को पूरा किया जायगा तथा 25 अन्य बैंक देहातों में स्थापित किए जायेंगे ।

यह सब होते हुए भी एक बात की तरफ ध्यान देना होगा-तिलहन और दलहन की आज देश में बहुत कमी है, उन की उपज को बढ़ाने के लिये खास तौर से व्यवस्था होनी चाहिये और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे कृषि वैज्ञानिकों की खोज से यह सम्भव हो सका है कि आलू जो अब तक केवल रबी में पैदा होता था, अब गरमी और रबी दोनों में पैदा हो सकेगा । बल्कि गर्मी में उस की पैदावार रबी के मुकाबले ज्यादा होना सिद्ध हुआ है । गर्मी में जो आलू पैदा किया जाता है, उस में रोग लगने की गुंजाइश कम है । इसी तरह से तिलहन की व्यवस्था करना जरूरी है । मुझे इस बात की खुशी है कि इन्दिराजी ने कतिपय मुख्य मंत्रियों को इस बात की हिदायत की है कि मूंगफली की पैदावार बढ़ाने के लिए खास तौर से व्यवस्था की जाए, और यह भी संभव हो गया है कि मूंगफली भी गर्मी में और रबी में, दोनों में पैदा हो सकती है और यह बात भी मालूम हुई है कि मूंगफली की पैदावार के लिए उतने पानी की जरूरत नहीं होती है जितना कि धान की पैदावार के लिए । इसलिए गर्मी में मूंगफली पैदा की जाए तो एक हैक्टेयर में धान के लिए जितने पानी की जरूरत है, उतना पानी तीन हैक्टेयर में मूंगफली पैदा करने के लिए काफी होगा । इस से थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है और आशा बंधती है कि तिलहन की पैदावार की तरफ खास तौर से ध्यान है और उस के लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं और इन्दिरा जी का भी उस की तरफ खास तौर से ध्यान है । इसलिए लोगों को पूरा विश्वास है कि जो तिलहनों

[श्री जयराम वर्मा]

और दलहनों की कमी हमारे बीच में है, उस को जल्दी पूरा करने की व्यवस्था की जाएगी ।

इन सब बातों के साथ-साथ कृषि के विकास के लिए आवश्यक व्यवस्था की गई है। उन व्यवस्थाओं के अलावा एक बात की और जरूरत है जिस से कि कृषि की पैदावार और बढ़ सके । वह यह है कि किसानों के दिलों में यह विश्वास पैदा होना चाहिए कि एग्रोकल्चरल प्राइसेस कमीशन सचमुच में उनके राहत का काम करता है। एग्रीकल्चरल प्राइसेज कमीशन का जो रूप इस समय है, उस से किसानों में उस के प्रति विश्वास नहीं रह गया है । मेरा आप से निवेदन है कि उस के रूप को आप बदलें और उस में कृषि वैज्ञानिक रखे जाएं, ऐसे लोग उस में रखे जाएं, जो गांवों की स्थिति से अवगत हों इस से किसानों का फिर से उस पर विश्वास हो जायेगा । उस के द्वारा जो कृषि उपज के दाम मुकर्रर होते हैं, उन को मुकर्रर करने में भी आसानी होगी और वह ज्यादा न्यायपूर्ण ढंग से कृषि उपज के दामों को तय कर सकेगा। जितनी मेहनत कर के जितना परिश्रम कर के किसान अनाज पैदा करता है, उस के सही दाम उस को मिल सकेंगे और जितनी, आशा हम उस से करते हैं कि वह पैदावार और बढ़ा दे, उस पैदावार को बढ़ाने में वह जरूर सफल होगा । यह भी जरूरी है कि जो पैदावार 1980-81 में हुई है, उस में जो वृद्धि हुई है उस को स्थिर करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए और कोशिश की जाए ताकि पैदावार में वृद्धि होती रहे ।

गांवों में किसानों के अतिरिक्त खेतिहर मजदूर, हरिजन, दस्तकार और जन जातियों के लोग भी हैं । उन के सुधार के लिए भी इस बजट में काफी व्यवस्था की गई है और इस से आशा है कि उन को आगे बढ़ने में काफी आसानी होगी और उन को प्रोत्साहन मिलेगा ।

गांवों में एक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिस में 1981-82 में 180 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । कुछ उधर के लोगों का यह ख्याल है कि शायद यह व्यवस्था पिछले साल के मुकाबले में कम की गई है लेकिन अगर गौर से देखा जाय, तो यह व्यवस्था कम नहीं की गई है । 180 करोड़ रुपए की व्यवस्था केन्द्र की तरफ से है और इतनी ही रकम की व्यवस्था राज्यों की ओर से की जायगी । इस तरह से कुल 360 करोड़ रुपये की व्यवस्था हो जायगी । पिछले साल 340 करोड़ रुपये की व्यवस्था थी लेकिन उस साल सिर्फ एक ही स्कीम थी । इस बजट में दूसरी स्कीमें भी शुरू की गई हैं ।

जो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, जिस के लिए 198 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है उस से यह आशा की जाती है कि तीस लाख परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाया जा सके ।

श्रीमान् जी, हरिजनों के लिए, या हरिजन जनजातियों के लिए इस के अतिरिक्त भी जो व्यवस्था की गई है, वह सचमुच आगे बढ़ाने में काफी सहायक होगी । लेकिन हमारी स्थिति ऐसी है कि हरिजनों के लिए संरक्षण का कायम रखना बहुत जरूरी है । मुझे इस बात की खुशी है कि सरकार अपने संवधानिक दायित्वों को समझती है और उन पर अडिग है और किसी तरह से भी उस के बारे में समझौता करना नहीं चाहती है । लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि गुजरात में कुछ लोगों ने इस संरक्षण के खिलाफ आन्दोलन छेड़ रखा है और वह आन्दोलन हिंसात्मक हो गया है । यह देश के लिए अच्छी बात नहीं है । कुछ लोग उस को हवा भी दे रहे हैं । मैं समझता हूं कि उस को हवा देना देश के खिलाफ काम करना है और देश का जो कमजोर वर्ग है उस वर्ग के हित के खिलाफ काम करना है इस में तो सभी राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त

होना चाहिए कि यह जो व्यवस्था हरिजनों के संरक्षण के लिए की गई है वह कायम रहे। कोई भी आदमी इस की मुखालिफत करे। मैं समझता हूं कि जो लोग इस आन्दोलन के पीछे हैं और इस को हिंसात्मक रूप दिए हुए हैं, वे अपने कदम को पीछे हटायेंगे और जो एक जरूरी चीज है उस में वे जो बाधा पदा किए हुए हैं, वह बाधा वे पैदा नहीं करेंगे।

इसी तरह से हरिजनों के अलावा अन्य पिछड़े वर्ग के लोग भी हमारे देश में काफी संख्या में रहते हैं। 1952 में राष्ट्रपति ने एक कमीशन उन के सम्बन्ध में नियुक्त किया था जिस की रिपोर्ट 1955 में आयी थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उस कमीशन की रिपोर्ट पर, उस की सिफारिशों पर जिस की अध्यक्षता एक गांधीवादी काका कालेलकर ने की थी, काम नहीं किया गया और उन सिफारिशों को माना नहीं गया। यह सौभाग्य की बात है कि एक दूसरा कमीशन श्री मण्डल जी की अध्यक्षता में नियुक्त हुआ। उस कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट अब दे दी है। अब मैं सरकार से, वित्त मंत्री के द्वारा यह निवेदन करना चाहूंगा कि अब जो रिपोर्ट आयी है, जिस के बारे में कहा जाता है उस में वे दोष नहीं हैं जो दोष पिछली रिपोर्ट में थे, उस पर सरकार को विचार कर के जल्दी ही उस की सिफारिशों को मंजूर करना चाहिए और इस सदन में और राज्य सभा में ले आना चाहिए ताकि उन पर विचार कर के कार्यवाही की जा सके। जिस से कि इस वर्ग को भी प्रोत्साहन मिले। मैं समझता हूं कि इन्दिरा जी को इस मामले में काफी दिलचस्पी है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have the support of the Opposition also in this regard—the only time they have supported you!

श्री जय राम वर्मा : इन्दिरा जी को पिछड़े वर्ग के लोगों से काफी हमदर्दी है और वे समझती हैं कि उन के लिए और उन के सुधार के लिए कुछ किया जाना आवश्यक है, नहीं तो उन की हालत और खराब हो जायेगी।

मैं यह कह सकता हूं कि पिछड़े वर्गों में कुछ जातियां ऐसी हैं जिनकी कि हरिजनों से भी सचमुच हालत खराब है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना होगा। यह एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसकी जनसंख्या, मैं समझता हूं, इस देश में 50 फीसदी से कम नहीं होगी। यह 50 फीसदी से ज्यादा ही होगी और 50 फीसदी समाज को अपेक्षित रखना ठीक नहीं होगा। यह समाज देश का एक बहुत बड़ा अंग है। उसको भी ऐसे साधन मिलें जिससे कि वह भी दूसरों के समकक्ष हो सके और समकक्ष हो कर के इस देश की सेवा पूरी शक्ति के साथ कर सकें।

श्रीमान् जी, समाज में तरह तरह के दोष मौजूद हैं। जातिवाद का जो जहर फैला हुआ है, उस जातिवाद के जहर को तभी दूर किया जा सकता है जबकि विभिन्न वर्गों के लोग समकक्ष हो जाएं। जब एक स्तर पर आ जाये; जब एक स्तर पर आ जायेंगे तो किसी भी जाति को इस बात की आवश्यकता नहीं होगी कि वह कोई विशेष सुविधा मांगें। न किसी जाति को अपमान मिलेगा, न विशेष सुविधा सम्मान मिलेगा। किसी को भी इस बात की फिक्र नहीं रहेगी। इसलिए यह जो एक जहर फैला हुआ है, इस जहर को दूर करने के लिए इन विभिन्न वर्गों के स्तर को करीब करीब एकसा करना होगा, तभी यह जहर दूर होगा, नहीं तो नहीं। यह जहर समाजवाद का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर समाजवाद स्थापित होना है तो इस जातिवाद के जहर को समाप्त करना होगा। इसके लिए रास्ता निकालना होगा और मैं समझता हूं कि इसका सबसे अच्छा

[श्री जय राम वर्मा]

रास्ता यही है कि जो असमानता है, उस असमानता को दूर किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि बजट में जनसंख्या के अनुरूप प्रदेशों के लिए धन का प्रावधान न करने की वजह से उनके विकास में असमानता आ गई है। इस असमानता को दूर करना जरूरी है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, बिहार हो, किसी के लिए भी जनसंख्या के अनुरूप व्यय की व्यवस्था नहीं की गई है और इसलिए ये पिछड़े गए हैं। उनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए इन प्रदेशों का खासतौर पर ध्यान रखा जाए और बजट में इस प्रकार की व्यवस्था की जाए जिससे उनका पिछड़ापन जल्दी ही दूर हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं फिर माननीय वित्त मंत्री महोदय को उनके विश्वास के लिए और उनके कौशल के लिए, जिससे उन्होंने यह बजट पेश किया है, बधाई देना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने यह बजट पेश किया है, उससे जनता के मन में वह विश्वास जिससे उन्होंने इंदिरा जी को सत्ता सौंपी है, और दृढ़ हो जाएगा।

श्री समीनुद्दीन (गोड्डा) : जनाबे सद्र, मैं आपका मश्कूर हूं कि निर्धारित समय निकलने के बाद भी आपने सामान्य बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया। हालिया बजट जो सदन में पेश किया गया है इस पर दो दिनों से तन्कीद और ताईद का सिलसिला जारी है। बाइक्तदार जमात की तरफ से ताईद होती रही और हिज्ब मुखालिफ की तरफ से तन्कीद होती है, लेकिन इसका फैसला कैसे हो कि यह बजट निहायत ही उम्दा और आइडियल बजट है। इसका फैसला तो कोई तीसरा आदमी ही कर सकता है। मैं 27, 28 फरवरी पहली, दूसरी मार्च को दुमका, भागलपुर गया था बार लायब्रेरियों में और कालेजों और स्कूलों में गया और बहुत से बुद्धिजीवियों से मिला। उन लोगों ने कहा कि वाकयी यह बजट जो सदन में 1981–82 को पेश हुआ है यह आइडियल बजट है। सारे लोगों ने मुझे मुबारकबाद दी और मैं उन सारे मुबारकबादियों को इकट्ठा करके लाया हूं और इस बात का इन्तजार था कि मैं उनको पेश करूं जिसको आज मैं उसको पेश कर रहा हूं। बजट की बहस में एक बात देखने में आई है कि चाहे कितने ही अच्छी बात की जाती हो, लेकिन फिर भी मुखालिफ पार्टी के लोग उसकी मुखालिफत करते हैं। बहरहाल, बजट भाषा देखने के बाद मुझे पता चला कि बजट भाषण में सारी चीजों की पैदावार में वृद्धि बताई गई है और इसमें अन्देशा जाहिर की गई है कि मुल्क की बढ़ती हुई आबादी हमारे बजट को बदनुमा कर सकती है, गड़बड़ा सकती है, हमारे कदमों को आगे बढ़ने से रोक सकती है। हमारा थाना थोरिया जिसमें पहले 80,000 की आबादी थी वह 1971–72 में बढ़ कर 95000 हुई। वहां काफी नसबन्दियां हुई हैं, फैमिली प्लानिंग का काम वहां बहुत अच्छा चला।

सब इससे मुत्तफिक थे। किसी को कोई इख्तलाक नहीं था। लेकिन इस बार 1980–81 मरदुम शुमारी हुई है उस में वहां की आबादी 1 लाख 20 हजार तक पहुंच गई है। जब मंसूबा हम चलाते हैं, नसबन्दियां हम करते हैं तो उसके बावजूद भी आबादी क्यों बढ़ रही है, इसकी गहराई में जाने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि इस नसबन्दी

की चार किस्में हैं । एक तो वे लोग हैं जो बासलाहियत हैं और जिनके लड़का लड़की हो सकता है उनकी नसबन्दी कर दी गई है, इनकी तादाद चार या पांच आना है । दूसरे लोगों की कर दी गई है जिन में सलाहियत ही नहीं थी । तीसरे वे हैं जिन को निशान लगाकर छोड़ दिया गया और चौथे वे हैं जिन के निशान भी नहीं लगाया गया है । लाखों लाख रुपया इस तरह से नसबन्दी के काम में बरबाद हुआ है । जिस वक्त यह प्लान नहीं थी उस वक्त तो आबादी कम बढ़ी लेकिन इस प्लान के बाद पच्चीस हजार आबादी बढ़ी है । इससे मुझे ऐसा लगता है कि या तो मंसूबा ठीक तरह से नहीं चल रहा है और अगर ठीक तरह से चल रहा है तो मैं यही कहूंगा कि खुदा इतनी हमारी कोशिशों के बाद भी नहीं चाहता है कि आबादी कम हो, बल्कि चाहता है कि आबादी बढ़ जाए । मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर की रजामन्दी इस में नहीं है । हम लोगों को इससे सबक लेना चाहिए ।

माभिन दावतिन अलल्लाहु रिजकुहा खुदा कहता है कि रोजी देने का जिम्मेदार मैं हूं । हो सकता है कि वह बिगड़ और गुस्सा हो गया हो । नसबन्दियां भी होती हैं लेकिन फिर भी आबादी घटती नहीं है बढ़ती चली जा रही है तो यह उसकी ही मर्जी है । मैं इस सिलसिले में कुछ सुझाव देना चाहता हूं । यह एक ऐसा मंसूबा है जिस में किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है, मुखालिफ तक को भी नहीं है । सब मानते हैं कि नसबन्दी ऐसे लोगों की की जाए जो बासलाहियत हों, जो बच्चा पैदा कर सकते हों निज निजायज तरीके से पैसा खर्च न किया जाए ।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि आजाद देश में रुपया दे कर नसबन्दी न की जाए बल्कि यह वालैंटरी और रजामन्दी से हो ।

तीसरा मेरा सुझाव यह है कि नसबन्दी करके उसको छोड़ न दिया जाए, बल्कि दो तीन रोज तक उसको बैड पर रखा जाए, और उसका इलाज किया जाए । तभी यह मंसूबा कामयाब हो सकता है ।

हमारे बजट को जो चीज नुक्सान पहुंचा सकती है वह ला एण्ड आर्डर की खराबी है । सारा रुपया सरकार देती हैं लेकिन अगर ला एण्ड आर्डर पर हमारा कंट्रोल नहीं है तो हमारे बजट को यह चीज बदनुमा कर सकती है, अमली जामा पहनाने से हम को रोक सकती है । मैं अपने जिले भागलपुर की बात करता हूं मेरे जिले में आज के पहले बहुत डकैतियां होती थीं । आंखें फोड़े जाने के मामले को ले कर यह जिला बड़ा मशहूर हो चुका है । 25 जुलाई, 1980 को मैंने एक लिस्ट पेश की थी जिसमें, डकैतियों का उल्लेख था जहां डकैतियां हुई थीं । सैकड़ों डकैतियों की वह लिस्ट थी । फिर यकायक डकैतियां रुकीं । और यह दो तीन महीने तक बन्द रहीं । मालूम यह हुआ कि चाहे पुलिस ने या अव्वाम ने डकैतों की आंखें निकाली हों उसकी वजह से इस पर रोक लगी । और डकैतियों का सिलसिला बन्द हुआ । मगर जब यह मामला फटा, कुछ पुलिस अफसर मुअत्तल किये गये, अधिकारियों को सजा दी गई और जिनकी आंखें निकाली गयीं थीं उनको इमदाद और इनाम दिया गया तो आज यह हाल है कि सरे आम राह चलना मुश्किल हो गया है । 6, 7 बजे शाम को दुकानें बन्द हो जाती हैं, रास्ता चलना मुश्किल हो गया है । आज सारे लोगों की निगाहें महंगाई पर नहीं हैं, बल्कि इस बात से परेशान हैं कि डकैतियों से किस तरह अपनी इज्जत ब

[श्री समीनुद्दीन]

आबरू बचायें । यह डकैतियां अमीरों के यहां ही नहीं बल्कि जिसके यहां दो मन चावल और 1 मन गेहूं भी है उसके यहां भी डकैती होती है और जराइम पेशा लोग नाजाइज और गलत हथियार ले कर घूमते रहते हैं, कोई पकड़ने वाला नहीं है । पुलिस चुप हो कर बैठ गई है, पुलिस का मनोबल गिर चुका है और डकैतों का मनोबल ऊपर उठ गया है । आज शरीफों की जिन्दगी दूभर हो गई है । इस तरफ सरकार ध्यान दे और जराइम पेशा के कानून में सुधार लाये ।

बिजली की कमी की वजह से पावरलूम और हैंडलूम की सन्तों को काफी धक्का पहुंचा है । जनता राज्य में और हमारे राज्य में भीपावरलूम नहीं चला सूत की कीमत बढ़ गई और जितने कर्जे सरकार ने दिये थे सब बेकार बुनकर खा गये । बिहार में बुनकरों की 1100 कोआपरेटिव सोसाइ-टियां हैं जिनमें लगभग 10 लाख बुनकर शामिल हैं । आज वह सारे के सारे परेशान हैं, उनकी कुर्की और जब्ती हो रही है । उन्होंने हमारे द्वारा दर्खास्तें दी, हमारे द्वारा उद्योग मंत्री और प्रधान मंत्री को दी हैं । मगर अभी तक कुछ नहीं हो रहा है । 10, 10 लाख बुन-करों का यह हाल है तो देश का क्या हाल होगा । इसलिये जिनके पास जमीन तक नहीं है उन बुनकरों के कर्जे माफ कर दिये जायें ।

हमारे क्षेत्र में बांसकूपी ज्यन्ती कोलियरी मधुपुर करांव सन्थाल परगना में है जो अंग्रेजों के साथ समय में चलती थी और वहां के लोग सुखी थे । मगर आज वह कोलियरी बन्द है । सारा सामान कोयला निकालने का वहां मौजूद है, उसके निगरां भी मौजूद हैं, उन को तनुख्वाह भी दी जाती है, मगर काम नहीं हो रहा है । मैं चाहता हूं कि उस कोलियरी को खोल दिया जाये ताकि उस आदिवासी क्षेत्र में लोगों को काम मिले और कोयला आसानी से मिल सके ।

चौथी बात यह है कि राजमहल लमटिया प्रोजेक्ट में जहां सुपर थर्मल पावर स्टेशन बनने जा रहा है जिसके लिये हजारों एकड़ जमीन ऐक्वायर की जायेगी । मगर अभी तक कोई संसद सदस्यों की कमेटी नहीं बनाई गई है जिसकी वजह से हालत यह है कि यूनि-यनबाजी चल रही है, कम्युनिस्टों तथा कांग्रेसियों की, झारखंड मुक्ती मोर्चा की, इन सब की अलग-अलग यूनियनें हैं जिनकी वजह से जमीन ऐक्वायर नहीं हो पा रही है । जब तक जमीन ऐक्वायर नहीं होगी तब तक सुपर थर्मल पावर स्टेशन कामयाब नहीं हो सकता है । इसलिये वहां एक एडवाइजरी कमेटी बनाई जाये और उसके जरिये जमीन ऐक्वायर की जाये, और वहां के कर्म-चारियों और मजदूरों की बहाली हो और सारा इन्तजाम किया जाये । यह सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे क्षेत्र से ताल्लुक रखती हैं । मंदार हिल जो बांसी से ले कर बैजनाथधाम तक 55 मील की दूरी है, जिसके बारे में मैंने सवाल किया था और मुझे जवाब दिया गया कि सारा काम उसका पूरा हो चुका है, अब इसमें सिर्फ रूपया देना बाकी है । मगर अफसोस है कि इस बार भी बजट में रूपया नहीं दिया गया है । हमारे क्षेत्र में कहीं रेलगाड़ी नहीं है । यह 55 मील की रेल लाइन अगर पूरी हो जाती है तो बैजनाथधाम का लिंक कलकत्ते से हो जायगा ।

बस मुझे इतना ही कहना था । आपने मुझे वक्त दिया इसके लिये मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और इन लफ्जों के साथ बजट की ताईद करता हूं ।

[شری سمین الدین (گوڈا)]:

جناب صدر - میں آپ کا مشکور ہوں کہ نردھارت سمے نکلنے کے بعد بھی آپ نے سامانئے بجٹ پر مجھے بولنے کا موقع دیا - حالیہ بجٹ جو سدن میں پیش کیا گیا ہے اس پر نو دنوں سے تنقید اور تائید کا سلسلہ جاری ہے - با اقتدار جماعت کی طرف سے تائید ہوتی رہی ہے اور حزب مخالف کی طرف سے تنقید ہوتی ہے لیکن اس کا فیصلہ کیسے ہو کہ یہ بجٹ نہایت ہی عمدہ بجٹ ہے اور آئڈیل بجٹ ہے - اس کا فیصلہ تو کوئی تیسرا آدمی ہی کر سکتا ہے - میں ۲۷-۲۸ فروری— پہلی دوسری مارچ کو دمکا بھاگلپور گیا بار لائبریریوں میں گیا تھا کالجوں اور اسکولوں میں گیا تھا اور بہت سے بدھی جیویوں سے ملا - ان لوگوں نے کہا کہ واقعی یہ بجٹ جو سدن میں ۱۹۸۱-۸۲ کا پیش ہوا ہے یہ آئڈیل بجٹ ہے - سارے لوگوں نے مجھے مبارکباد دی اور میں ان ساری مبارکبادیوں کو اکٹھا کرکے لایا ہوں اور اس بات کا انتظار تھا کہ میں ان کو پیش کروں جس کو آج میں اس کو پیش کر رہا ہوں - بجٹ کی بحث میں ایک بات دیکھنے میں آئی ہے کہ چاہے کتنی ہی اچھی بات کی جاتی ہوں لیکن پھر بھی مخالف پارٹی کے لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں - بہر حال بجٹ بھاشن دیکھنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ بجٹ بھاشن میں ساری چیزوں کے پیداوار میں وردھی بتائی گئی ہے اور اس میں اندیشہ ظاہر کی گئی ہے کہ ملک کی بڑھتی ہوئی آبادی ہمارے بجٹ کو بد نما کر سکتی ہے گڑبڑا سکتی ہے ہمارے قدموں کو آگے بڑھنے سے روک سکتی ہے - ہمارا توانا دھوریا جس میں میں پہلے ۸۰۰۰۰ کی آبادی تھی وہ ۱۹۶۰ع-۱۹۶۱ع میں بڑھ کر صرف ۹۵۰۰۰ ہوئی - وہاں کافی نسبندیاں ہوئی ہیں - فیملی پلاننگ کا کام وہاں بہت اچھا چلا - سب اس سے متفق تھے - کسی کو کوئی اختلاف نہیں تھا - لیکن اس بار ۱۹۸۰-۸۱ میں مردم شماری ہوئی ہے اس میں وہاں کی آبادی ایک لاکھ بیس ہزار تک پہنچ گئی ہے - جب منصوبہ ہم چلاتے ہیں نس بندیاں ہم کرتے ہیں تو اس کے باوجود بھی آبادی کیوں بڑھ رہی ہے اس کی گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس نس بندی کی چار قسمیں ہیں - ایک تو وہ لوگ ہیں جو با صلاحیت ہیں اور جن کے لڑکا لڑکی ہو سکتا ہے ان کی نس بندی کر دی گئی ہے - ان کی تعداد چار یا پانچ آنا ہے - دوسرے ان لوگوں کی کر دی گئی ہے جن میں صلاحیت

[شری شہاب الدین]

ہی نہیں تھی - تیسرے وہ ہیں جن کو نشان لگا کر چھوڑ دیا گیا اور چوتھے وہ ہیں جن کے نشان بھی نہیں لگایا گیا ہے - لاکھوں لاکھ روپیہ اس طرح سے نس بندی کے کام میں برباد ہوا ہے - جس وقت یہ پلان نہیں تھی اس وقت تو آبادی کم بڑھی تھی لیکن اس پلان کے بعد ۲۵ ہزار آبادی بڑھی ہے - اس سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کیا یا تو منصوبہ ٹھیک طرح سے نہیں چل رہا ہے اور اگر ٹھیک طرح سے چل رہا ہے تو میں یہی کہوں گا کہ خدا ہماری اتنی کوششوں کے بعد بھی نہیں چاہتا ہے کہ آبادی کم ہو بلکہ چاہتا ہے کہ آبادی بڑھ جائے - مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایشور کی رضامندی اس میں نہیں ہے - ہم لوگوں کو اس سے سبق لینا چاہئے -

"وما من دابۃ الا رزقها"

خدا کہتا ہے کہ روزی دینے کا ذمہ‌دار میں ہوں - ہو سکتا ہے کہ وہ بگڑ اور غصہ ہو گیا ہو - نس بندیاں بھی ہوتی ہیں لیکن پھر بھی آبادی گھٹتی نہیں ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے تو یہ اسی کی ہی مرضی ہے - میں اس سلسلے میں کچھ سجھاؤ دینا چاہتا ہوں - یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے - مخالفت کو بھی نہیں ہے سب مانتے ہیں کہ نس بندی ایسے لوگوں کی کی جائے جو با صلاحیت ہوں جو بچے پیدا کر سکتے ہوں - نیز ناجائز طریقے سے پیسہ خرچ نہ کیا جائے -

دوسرا میرا سجھاؤ یہ ہے کہ آزاد دیش میں روپیہ دے کر نس بندی نہ کی جائے بلکہ یہ والینٹری اور رضامندی سے ہو -

تیسرا میرا سجھاؤ یہ ہے کہ نس بندی کرکے اس کو چھوڑ نہ دیا جائے بلکہ دو تین روز تک اس کو بیڈ پر رکھا جائے اور اس کا علاج کیا جائے - تبھی یہ منصوبہ کامیاب ہو سکتا ہے -

ہمارے بجٹ کو جو چیز نقصان پہنچا سکتی ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی خرابی ہے - سارا روپیہ سرکار دیتی ہے لیکن اگر لا اینڈ آرڈر پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے تو ہمارے بجٹ کو یہ چیز بدنما کر سکتی ہے عملی جامہ پہنانے سے ہم کو روک سکتی ہے - میں اپنے ضلع بھاگلپور کی بات کرتا ہوں - میرے ضلع میں آج سے پہلے بہت ڈکیتیاں ہوتی تھیں - آنکھ پھوڑے جانے کے معاملے کو لے کر یہ ضلع بڑا مشہور ہو چکا ہے - ۲۵ جولائی ۱۹۸۰ کو میں نے ایک لسٹ پیش کی تھی جس میں ڈکیتیوں کا تذکرہ تھا جہاں ڈکیتیاں ہوتی تھیں - سیکڑوں ڈکیتیوں کی وہ

بجلی کی کمی کی وجہ سے پاورلوم اور ہینڈلوم کی صنعتوں کو بہت دھکا پہنچا ہے - جنتا راج میں اور ہمارے راج میں بھی پاور لوم نہیں چلے سوت کی قیمت بڑھ گئی اور جتنے قرض سرکار نے دیئے تھے سب بیکار بنکر کھا گئے - بہار میں بنکروں کی ۱۱۰۰ کوآپریٹیو سوسائٹیاں ہیں جن میں لگ بھگ ۱۰ لاکھ بنکر شامل ہیں - آج وہ سارے کے سارے پریشان ہیں ان کی کوکی اور ضبطی ہو رہی ہے - انہوں نے ہمارے دوارا درخواستیں انڈسٹریز منسٹر اور پرائم منسٹر کو دی ہیں مگر ابھی تک کچھ نہیں ہو رہا ہے - ۱۰ - ۱۰ لاکھ بنکروں کا یہ حالت ہے تو دیش کا کیا حال ہو گا - اس لئے جن کے پاس زمین تک نہیں ہیں ان بنکروں کے قرض معاف کر دیئے جائیں -

ہمارے چھیتر میں بانس کرپی چونکتی ء کولیری مدھوپور کرانو سنتھال پرگنہ میں ہے جو انگریزوں کے سمے میں چلتی تھی اور وہاں کے لوگ سکھی تھے - مگر آج وہ کولیری بند ہیں - سارا سامان کوئلہ نکالنے کا وہاں موجود ہے اس کے نگران بھی موجود ہیں ان کو تنخواہ بھی دی جاتی ہے مگر کام نہیں ہو رہا ہے - میں چاہتا ہوں کہ اس کولیری کو کھول دیا جائے

لسمٹ تھی - پھر یکایک ڈکیتیاں رکیں اور یہ دو تین مہینے تک بند رہیں - معلوم یہ ہوا کہ چاہے پولس نے یا عوام نے ڈکیتوں کی آنکھیں نکالیں ہوں اس کی وجہ سے ان پر روک لگی اور ڈکیتیوں کا سلسلہ بند ہوا - مگر جب یہ معاملہ پھٹا ، کچھ پولس افسر معطل کئے گئے - ادھیکاریوں کو سزا دی گئی اور جن کی آنکھیں نکالی گئیں تھیں ان کو امداد اور انعام دیا گیا تو آج یہ حال ہے کہ سرشام راہ چلنا مشکل ہو گیا ہے - چھ سات بجے شام کو دوکانیں بند ہو جاتی ہیں راستہ چلنا مشکل ہو گیا ہے - آج سارے لوگوں کی نگاہیں مہنگائی پر نہیں ہیں بلکہ اس بات سے پریشان ہیں کہ ڈکیتوں سے کس طرح سے اپنی عزت و آبرو بچائیں - یہ ڈکیتیاں امیروں کے یہاں ہی نہیں بلکہ جس کے یہاں دو من چاول اور ایک من گیہوں بھی ہے اس کے یہاں بھی ڈکیتی ہوتی ہے اور جرائم پیشہ لوگ ناجائز اور غلط ہتھیار لے کر گھومتے رہتے ہیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے - پولس چپ ہو کر بیٹھ گئی ہے پولس کا مورل گر چکا ہے اور ڈکیتوں کا مورل اوپر اٹھ گیا ہے - آج شہریوں کی زندگی دوبھر ہو گئی ہے - اس طرف سرکار دھیان دے اور جرائم پیشہ کے قانون میں سدھار لائے -

[شری سمیں الدین]

تاکہ اس آدی واسی چھیتروں میں لوگوں کو کام ملے اور کوئلہ آسانی سے مل سکے -

چوتھی بات یہ ہے کہ راج محل پروجیکٹ میں جہاں سپر تھرمل پاور استیشن بنائے جا رہے ہیں جس کے لئے ہزاروں ایکڑ زمین ایکوائر کی جائے گی - مگر ابھی تک کوئی سنسد سدسیوں کی کمیٹی نہیں بنائی گئی ہے جس کی وجہ سے حالت یہ ہے کہ یونین بازی چل رہی ہے کمیونسٹوں اور کانگریسیوں کی جہار کھنڈ مکتی مورچا کی ان سب کی الگ الگ یونینیں ہیں جن کی وجہ سے زمین ایکوائر نہیں ہو پا رہی ہے - جب تک زمین ایکوائر نہیں ہو گی تب تک سپر تھرمل پاور اسٹیشن کامیاب نہیں ہو سکتا ہے - اس لئے وہاں ایک ایڈوائزری کمیٹی بنائی جائے اور اس کے ذریعہ زمین ایکوائر کی جائے اور وہاں کے کرمچاریوں اور مزدوروں کی بحالی ہو اور سارا انتظام کیا جائے - یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے چھیتر سے تعلق رکھتی ہیں - سلدار ہل جو بانسی سے لے کر بیجناتھ دھام تک 55 میل کی دوری ہے جس کے بارے میں میں نے سوال کیا تھا اور مجھے جواب بھی دیا گیا تھا کہ سارا کام اس کا پورا ہو چکا ہے ب اس میں صرف روپیہ دینا باقی ہے - مگر افسوس ہے کہ اس بار بھی بجٹ میں روپیہ نہیں دیا گیا ہے - ہمارے چھیتر میں کوئی ریل گاڑی نہیں ہے یہ 55 میل کی ریل لائن اگر پوری ہو جاتی ہے تو بیجناتھ دھام کا لنک کلکتہ سے ہو جائے گا -

بس مجھے اتنا ہی کہنا تھا - آپ نے مجھے وقت دیا اس کے لئے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان لفظوں کے ساتھ بجٹ کی تائید کرتا ہوں -]

19 hrs.

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, बजट बहुत संतुलित प्रस्तुत किया गया है, जिससे मध्यम और निम्न श्रेणी के लोगों को काफी लाभ मिलेगा, इसलिए इसका मैं स्वागत और समर्थन करता हूं।

इस बजट से बचत की भी बहुत बड़ी संभावना है और इन्वेस्टमैंट भी काफी होगा जिससे हमारे देश की औद्योगिक प्रगति काफी तेजी से हो सकेगी।

मैं खास तौर से कुछ बातें निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है इसलिए विशेष रूप से उसमें न जा कर एक प्वाइण्ट पर विशेष ध्यान दिलाना चाहूंगा। रीजनल इम्बैलेन्सेज जो हमारे देश में हैं इसके सम्बन्ध में वित्त मंत्री महोदय को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।

राजस्थान एक पिछड़ा हुआ प्रान्त है और उसमें भारत सरकार ने 2 प्रतिशत

से भी कम पैसा पब्लिक सैक्टर में इन्वेस्ट किया है। इससे इसकी जो प्रगति होनी चाहिए, वह नहीं हुई है। राजस्थान एक ऐसा प्रान्त है, जहां प्राकृतिक साधन, मिनरल्स बहुत बड़ी माला में उपलब्ध होती हैं, कौपर, जिंक आदि अनेक प्रकार की चीजें हैं। इनके सम्बन्ध में अभी तक भी किसी प्रकार की कोई खास व्यवस्था नहीं की गई है।

अभी थोड़े दिन पहले आगूचा में जिंक का एक बहुत बड़ा भंडार मिला है जिसको कहते हैं कि एशिया में बहुत बड़ा भंडार यह है। वहां पर कोई औद्योगिक ईकाई नहीं लगी यानी जिंक स्मैल्टर प्लान नहीं लगा। अगर इसको अन्य स्थानों पर लगाया जायेगा तो वह एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। इसलिए वित्त मंत्री इस बात का ध्यान करें कि यह जो इतना बड़ा एरिया है और इतने बड़े डिपाजिट्स राजस्थान में हैं, निश्चित रूप से आगूचा में एक प्लान्ट लगाना चाहिए जिससे 15 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा और उसके साथ साथ औद्योगिक दृष्टि से भी काफी पनपने की संभावना है।

इसके अलावा भीलवाड़ा में माइका का बहुत बड़ा काम है। बिहार के बाद अगर दूसरा नम्बर आता है तो भीलवाड़ा का आता है, यहां माइका का इतना बड़ा भंडार है, उत्पादन है जिससे करोड़ों रुपया फारेन-एक्सचेंज का मिलता है। इसका जो कूड़ा-करकट और कचरा रह जाता है, उसका भी बहुत विशाल भंडार यहां है। अब नये तरीके से माइका के वेस्ट का पेपर बनाने के कारखाने एक दो जगह स्वीकृत हुए हैं। एक बिहार में स्वीकृत हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूं कि जब इतना बड़ा भंडार माइका के वेस्ट का भीलवाड़ा में है तो निश्चित रूप से माइका के पेपर बनाने का कारखाना भीलवाड़ा में स्थापित होना चाहिए ताकि उसके जरिये सैकड़ों लोगों को रोजगार, धंधा मिल सके और जो सैकड़ों बरसों से माइका का वेस्ट पड़ा हुआ है, उसका भी उपयोग हो सके जिससे फारेन-एक्सचेंज में काफी सहायता मिल सकेगी। इस प्रकार की व्यवस्था निश्चित तरीके से की जानी चाहिए।

राजस्थान में कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा चित्तौड़ और मध्य प्रदेश का नीमच और मन्दसौर डिस्ट्रिक्ट हैं, ये 4, 5 डिस्ट्रिक्ट कन्टीन्यूएशन में हैं। इनमें चूने के पत्थर का विशाल भंडार है। अभी आपने 2 सीमेंट फैक्टरी भीलवाड़ा और चितौड़ में खोलने की स्वीकृति दी है, मगर यहां इतना बड़ा भंडार है कि अगर 10, 15 सीमेंट फैक्टरी भी लगाई जायें तो उनके लिए पर्याप्त माला में यहां चूने का पत्थर मौजूद है। इसलिए सीमेंट की कमी को देखते हुए अगर ज्यादा पैमाने पर वहां कारखाने लगाये जायेंगे तो उससे हमारे देश को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और उस क्षेत्र के लोगों को रोजगार व धन्धा भी मिल सकेगा। और औद्योगिक दृष्टि से भी हम काफी आगे बढ़ सकते हैं।

सरकार ने एल आई सी को पांच जोन्स में बांटने का जो फैसला किया है, वह एक बड़ा स्वागत-योग्य कदम है। उसमें बड़े घपले थे। वह एक बहुत विशाल यूनिट बन गया था इसलिए उसको पांच टुकड़ों में बांटने से व्यवस्था में सुधार होगा। लेकिन एक और संस्था है, जिसमें इससे भी ज्यादा घपले हैं, और वह है प्राविडेंट फंड की संस्था। मालिकों द्वारा मजदूरों से करोड़ों रुपये वसूल किये जाते हैं और वे उस रकम को डकार जाते हैं, खा जाते हैं। वह रकम सरकार के खजाने में जमा नहीं होती है। जितना पैसा मजदूरों से वसूल होता है, उतना ही पैसा मालिकों

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

को अपनी तरफ़ से जमा कराना होता है। इन दोनों प्रकार के पैसे को अपने पास रख कर इंडस्ट्रियलिस्ट्स आज तक मजदूरों का शोषण कर रहे हैं।

हमने कई दफ़ा पार्लियामेंट में यह सवाल उठाया है। मजदूरों को दस दस बरस तक रसीद नहीं मिलती है। प्राविडेंट फण्ड कमिश्नर ने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स पर लाखों रुपये का जुर्माना भी किया, लेकिन न तो वह जुर्माना और न प्राविडेंट फण्ड का पैसा जमा किया जाता है। जब कारखाने में मजदूर की नौकरी खत्म होती है, तो उसके पास रसीद न होने की वजह से उसको प्राविडेंट फण्ड का पैसा उपलब्ध नहीं हो पाता है। यह एक बहुत बड़ा घोटाला है। विभाग द्वारा इस बारे में कोई सतर्कता नहीं बरती जाती है। अगर इस संस्था को तीन, चार या पांच में बांट दिया जाये, तो इसकी व्यवस्था सुचारु रूप से चलेगी, मजदूरों का पैसा सुरक्षित हो जायेगा, उनकी कठिनाई दूर हो जायेगी और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स जो करोड़ों रुपये खा रहे हैं, सरकार के पास जाने से उनका सही उपयोग हो सकेगा।

हम लोग राजस्थान कैनाल के बारे में बार-बार निवेदन करते हैं, लेकिन उसकी तरफ़ कोई तवज्जुह नहीं दी जाती है। उसके लिए पूरा पैसा नहीं मिल रहा है। वह काम दस बरस में पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन वह बीस बरस में भी नहीं हो पाया है। अभी उसका पहला फ़ेज ही खत्म हुआ है और दूसरा फ़ेज चल रहा है। जिस स्कीम के द्वारा अधिक अन्न उपजा कर हम सारे देश के लोगों को खिलाना चाहते हैं, वह अभी तक ठंडी पड़ी हुई है। भारत सरकार उसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है इसलिए वह स्कीम रेंगते रेंगते चल रही है। यह एक बहुत बड़ी नेशनल प्राजेक्ट है, जिससे लाखों एकड़ जमीन सिंचित होगी। इसके लिए विशेष रूप से प्रावधान कर के इसे तेजी से पूरा करना चाहिए।

हमारे यहां जो बांध बने हुए हैं, उनकी नहरें और पानी निकलने के अन्य स्रोत बिल्कुल कच्चे हैं। इसलिए आधा पानी वेस्ट हो जाता है। अगर नहरों को पक्का करें, तो निश्चित रूप से एक ही वर्ष में इरिगेशन दुगनी हो जायेगी और उससे हमारी पैदावार में बहुत वृद्धि होगी। मेरे जिले में खारी, सरेरी, अरवड़ और मेज, ये चार मीडियम-साइज के बांध हैं। अगर उनकी नहरों को पक्का कर दिया जाये, तो हमारे क्षेत्र को बहुत लाभ होगा।

जिन क्षेत्रों में अकाल पड़ता है, वहां डी पी ए पी चलाया जाता है। मेरे जिले के एक तरफ अजमेर है और दूसरी तरफ़ उदयपुर है। उन दोनों में यह प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन उन दोनों के बीच स्थित भीलवाड़ा को छोड़ दिया गया है। वहां हर दूसरे साल अकाल पड़ता है। डी पी ए पी के अन्तर्गत सहायता न मिलने के कारण इस जिले के लोगों को काफ़ी कष्ट है। इसलिए मेरा निवेदन है कि भीलवाड़ा जिले को भी डी पी ए पी में लिया जाए, ताकि वहां के लोगों को राहत मिल सके और उनकी कठिनाइयां दूर हो सकें।

पब्लिक सैक्टर में कई जगह बड़े घोटाले हैं। मैंने पार्लियामेंट में कई दफ़ा यह सवाल उठाया है कि 1978 में कापर प्राजेक्ट, खेतड़ी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उन्होंने मिली-भगत कर के वहां पर निकले कापर के परसेंटेज को कम बताया, जिसकी वजह से 21 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ। एक प्रश्न के उत्तर में पार्लियामेंट में बताया गया कि एक कमेटी

द्वारा उसकी जांच हो रही है । जांच कब तक होगी ? किस प्रकार की व्यवस्था होगी ? तीन वर्ष तो पूरे हो चुके । तीन वर्ष के अन्दर इस घोटाले की कोई व्यवस्था नहीं हो सकी जो जनता पार्टी के समय का है । जनता पार्टी के मिनिस्टर से ले कर वहां के जनरल मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर और जितने अधिकारी लोग हैं वे सब उस में इन्वाल्वड हैं । इतने बड़े घोटाले के सम्बन्ध में भी अगर भारत सरकार कोई ऐक्शन नहीं लेती और उसके सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करती तो निश्चित तरीके से मैं यह कह सकता हूं कि पब्लिक सेक्टर कभी पनप नहीं सकता है । इस प्रकार के सफ़ेद हाथी आप ने वहां बैठा रखे हैं जो मनमानी करते हैं और पुराने जमाने के बादशाहों से भी ज्यादा ठाट बाट से वे आज रहते हैं । इस प्रकार के लोगों के खिलाफ निश्चित तरीके से काम किया जाना चाहिए ।

आपने कोयले और लोहे की कीमत बढ़ा दी । इसलिए कोयले और लोहे से थोड़े दिन आप को फायदा दिखेगा । मगर पैसे बढ़ाने के बजाय अगर ऐडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट हमारा ठीक होता तो निश्चित तरीके से इस पब्लिक सेक्टर के जरिए से हम बहुत बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते थे । की-इण्डस्ट्रीज को आपने पब्लिक सेक्टर में लिया है जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है । इस प्रकार के कारखानों को अगर हम ठीक प्रकार से चलाते हैं तो देश को बहुत बड़ा लाभ होगा । लेकिन उस लाभ से आज हम वंचित हैं ।

पब्लिक सेक्टर में जो स्टील के कारखाने हैं उन में तो नुकसान है पर जो उनके एजेंट हैं वे आज लखपति और करोड़पति बन गए हैं । वह इसलिए कि उन की मैनेजमेंट के साथ मिली भगत है, इसलिए सस्ते दामों पर स्टील प्राप्त कर के उन का ज्यादा से ज्यादा पैसा प्राप्त करते हैं और अपने आप को धनाढ्य बनाने की बराबर कोशिश करते हैं । सरकार को इन सारी बातों पर निगाह रखनी चाहिए । अगर आप निगाह रखेंगे तो निश्चित तरीके से हमारे पब्लिक सेक्टर कभी भी नुकसान नहीं दे सकते । इतने बड़े विशाल पैमाने पर आप ने इस में रुपया लगाया है । 15 हजार करोड़ रुपया कोई कम नहीं है । इसके ब्याज से आप इस सारे देश को रोशन बना सकते थे, इसको आर्थिक तौर पर मजबूत बना सकते थे । लेकिन इतनी बड़ी रकम लगाने के बाद भी कभी चार सौ करोड़ का नुकसान कभी पांच सौ करोड़ का नुकसान इस में हो रहा है । जब कि आप की मोनोपली है, आप के सिवाय उस प्रकार के काम में और कोई काम नहीं कर सकता, उस हालत में भी अगर पब्लिक सेक्टर हमें नुकसान देता है तो निश्चित तरीके से यह हमारी कमजोरी और हमारी कमी है जिस के कारण हमें यह नुकसान हो रहा है । इसलिए इस सम्बन्ध में तवज्जह देना चाहिए, अच्छे, योग्य और ईमानदार लोगों को वहां बैठाना चाहिए न कि ऐसे लोगों को जिन्होंने आज वहां एक तमाशा बना रखा है । पब्लिक सेक्टर में जितने लोग बैठे हैं, आज किस तरीके से उन की मिली-भगत है वह मैं बताता हूं । इधर तो मार्किसस्ट कम्यूनिस्ट पार्टी और कम्यूनिस्ट पार्टी के लोग मजदूरों में घुसे हुए हैं और इधर उन्हीं से मिले हुए लोग मैनेजमेण्ट में बैठे हुए हैं । इन की मिली-भगत की वजह से रोज हड़तालें होती हैं, रोज काम बन्द होता है जिससे कितना नुकसान पब्लिक सेक्टर को हो रहा है इसका आप अन्दाज नहीं लगा सकते । इस तौर तरीके की व्यवस्था चल रही है और यहां पर दूसरे लोग जो सरकार से सहानुभूति रखते हैं, जो सरकार के हाथ मजबूत करना चाहते हैं उस प्रकार

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

के जो ट्रेड यूनियन में काम करने वाले लोग हैं उन को प्रेफरेंस नहीं मिलता, उनको उनका ड्यू शेयर नहीं मिलता । उनकी व्यवस्थाओं को कमजोर करने के लिए उनको विक्टिमाइज किया जाता है, उनके साथ अन्याय और अत्याचार किया जाता है । इन सारी बातों को निश्चित तरीके से देखा जाना चाहिए, तभी जाकर आपका पब्लिक सेक्टर पनप सकता है ।

इसी तरह से आप का रोडवेज और एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है । कौन सी स्टेट में आप के रोडवज और एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फायदे में हैं । तमाम के तमाम नुकसान में चल रहे हैं । करोड़ों रुपये का घाटा सब जगह है जब कि आप की मोनोपली है । मोनोपली होने के बाद में यह हालत है । अगर प्राइवेट सेक्टर में यह होते तो करोड़ों रुपये का फायदा निश्चित तरीके से वह इस रोडवेज और एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जरिए उठा सकता था । मगर आप की मोनोपली होते हुए आप सब जगह करोड़ों रुपये का नुकसान उठा रहे हैं । इसलिए इन व्यवस्थाओं को ठीक किया जाना चाहिए, इस को मजबूत किया जाना चाहिए । जो लीकेज है उसको बन्द किया जाना चाहिए तब जाकर हमारी सारी व्यवस्था ठीक होगी ।

डिस्ट्रिब्यूशन के सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं । आप कितनी ही कोशिश करें डिस्ट्रिब्यूशन की व्यवस्था ठीक प्रकार से चल नहीं सकेगी जब तक कि आप कोआपरेटिव्स को गांवों के अन्दर मजबूत नहीं करेंगे । कोआपरेटिव्ज किस प्रकार से मजबूत कर सकते हैं ? उन को आप पैसा दीजिए ताकि वे एसैंशियल आर्टिकल्स खरीद कर सप्लाई कर सकें । इस प्रकार की व्यवस्था जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप का कोआपरेटिव सेक्टर चल नहीं सकता । उनके पास एक छदाम भी नहीं है एसैंशियल आर्टिकल्स को खरीदने के लिए, कैसे वह सार्वजनिक वितरण का काम कर सकेंगे । इसलिए कम से कम 5 सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था उनके लिए कीजिए अगर सारे देश में एसैंशियल कमोडिटीज ठीक प्रकार से लोगों को सप्लाई करना चाहते हैं तब जाकर हम इस व्यवस्था को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बना सकते हैं ।

मैं एक निवेदन आप से यह करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर नर्मदा के पानी का बंटवारा होना चाहिए था और पहले जो ऐग्रीमेंट हुआ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकारों के बीच में उस समय हम को यह कहा गया था कि 5 लाख फुट पानी आप को दिया जाएगा । उसके बाद में कराड़ा बांध उन्होंने बना लिया । गुजरात ने तो अपना काम कर लिया, सारा पानी ले लिया । जो हमारा हिस्सा मिलना चाहिए था वह हिस्सा आज तक नहीं मिला । उसके हिस्से में झगड़ा डाल दिया जिससे कि बाड़मेर और जालौर, दो जिले सिंचित हो सकते थे । इस प्रकार से उनको वंचित कर दिया गया । मैं प्रार्थना करूंगा कि इसके सम्बन्ध में दोबारा गौर किया जाए और नर्मदा का जो पानी राजस्थान को मिलना चाहिए वह उसको मिले । राजस्थान के पिछड़े हुए डेजर्ट एरिया—बाड़मेर और जालौर को पानी जरूर मिलना चाहिए ताकि वहां की व्यवस्था ठीक हो सके ।

थीन डैम के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं । हालांकि अभी फैसला नहीं हुआ है लेकिन उसमें राजस्थान, हरियाणा और पंजाब—तीनों का ही हिस्सा होना चाहिए । राजस्थान को उसमें से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है जो कि उचित नहीं है । आज भी राजस्थान पावर के मामले में बहुत पीछे है । वहां पर पीने के

पानी को पहुंचाने के लिए भी बिजली नहीं मिल पाती है और कारखाने बन्द हो रहे हैं। खेती के लिए 40 परसेण्ट से कम बिजली मिलती है। केवल 5-6 घण्टे बिजली मिलती है और वह भी रुक रुक कर। इसलिए थीन डैम के पानी और बिजली में राजस्थान को उसका ड्यू शेयर मिलना ही चाहिए।

बैंकों के सम्बन्ध में भी मेरा एक निवेदन है। गांवों में जो आपने बैंक खोले हैं वहां पर एक मैनेजर रखा है जो कि इधर उधर गांवों में जाता नहीं है और गरीबों को ऋण देता नहीं है जिससे लोगों को बहुत तकलीफ है। इसलिए उन बैंकों में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कि दूर के स्थानों के गरीब लोगों को भी पैसा मिल सके।

प्रोहिबिशन के सम्बन्ध में भी मुझे कुछ निवेदन करना है। प्रोहिबिशन के माध्यम से सरकार एक आदर्श स्थापित करना चाहती थी लेकिन वह तो हुआ नहीं अलबत्ता घर घर में शराब बनने लगी है। इस योजना के कारण विभिन्न राज्यों को कम से कम दो हजार करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है। इसके बावजूद जिस आदर्श को ले कर यह निर्णय लिया गया था उसकी पूर्ति न हो कर उल्टे घर घर में शराब बन रही है। दूसरी ओर स्टेट्स की फाइनेंसेज को घाटा होने से अन्य योजनायें भी लागू नहीं हो पा रही हैं। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। मैं प्रोहिबिशन के खिलाफ नहीं हूं लेकिन जब घर घर में शराब बनती हो और लोग शराब पीकर मरते हों तो उसको रोकने की व्यवस्था होनी चाहिए और स्टेट्स के लिए भी पैसे की व्यवस्था होनी चाहिए।

मैं अन्त में एक निवेदन और करना चाहूंगा कि आपने यू० पी०, हरियाणा तथा अन्य प्रदेशों के लिए अनेक खाद कारखानों की व्यवस्था कर दी परन्तु राजस्थान को यूं ही छोड़ दिया। राजस्थान को भी एक खाद का कारखाना मिलना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि इन बातों को आप स्वीकार करेंगे और पिछड़ेपन के कारण, राजस्थान में जो रीजनल इम्बैलेन्स है, उसको दूर करने तथा उसको आगे बढ़ाने में निश्चित तरीके से योगदान देंगे। इन शब्दों के साथ ही मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

SHRI S. B. SIDNAL (Belgaum): Sir, I firstly congratulate the Prime Minister and the Finance Minister for giving a production oriented budget this year. The budget should always try to create a just society in the country and lessen the economic disparities amongst all sections. Looking to this, our Finance Minister has placed a budget which is a historical one and which is going to build a new India in the coming days.

I would like to place before the House a few points about agriculture and small-scale industries. To improve agricultural production, so many projects have been taken up. So many irrigation dams have been built. But utilisation has not been properly made. With this view I would like to propose to the Government to open more technical schools because agriculture is now more scientific rather than an ordinary or traditional one. The agriculturists do not know how to make use of water, pesticides, inputs and soil testing. So many things are there to study. Eevry taluka should have one technical school wherein allied professions of the agriculture like dairy farming, poultry farming, piggery farming, sericultue, bee-keeping and such other subjects should be taught. This will not only improve the economic condition of rural India but it will solve the problem of unemployment. Instead of giving general education and creating white collar people, we

[Shri S. B. Sidnal

have to introduce technical schools. If you start such technical schools, the agriculturists having dry farming, will be busy throughout the year. Now, he is busy only two months in a year—one month at the time of sowing and another month at the time of harvesting. For the rest of the period he has to waste his energy. If we have such technical schools, we can provide jobs to the rural people thrughtout the year.

About introducing small scale industries, much has been discussed on the floor of this House, outside and in many academic councils. But nothing has happened. There is no progress. We have to see that the rural youth should be trained properly first and then given industry. Otherwise, voluntarily only a few will come and that too from the afflueunt sections and thus they will deprive them of the benefits given by the Government to the lower strata of the society. The educated boys from SC & ST, backward classes and adivasis should be trained in small scale industries and then asked to start industry. Unless they are trained, they will not produce.

With that my proposal will be to open a special department to take care of the SC & ST and Adivasi graduates and train them for a year or two and then give them some small scale industries. That will be helping the other sections to beg employed and those pair of hands should be helping the production of this country.

Regarding agriculture, we have made use of the river water, nala water and other water. But we have not been able to tap the underground water. The experts say that abundant water is available under the ground. We have not got sufficient rig machines to bore wells. Even we have not been able to provide drinking water to the people, what to talk of irrigation. A small country like Israel has been able to introduce underground sprinklers to feed the roots. You can look to any developed country. First, they developed their agriculture because it gives production, raw material, employment and keeps the people contended.

The disparity between village sector and city sector is growing. To stop this, we have to build up parallel cities and stop issuing licences in big cities. Contrary to it, the city is growing and village is diminishing. I have seen in the last 15 years dilapidated houses in the villages and multi-storeyed buildings coming up in the cities. Nehru told us that unless we develop our villages our economy will not develop because 80 per cent of our population depends only on agriculture and lives in rural areas. I do not say that the Government has neglected it. I think, the Government has allotted a good budget for it. But still it is not adequate to meet the rural development of this country. I thank the Government for having opened branches of nationalised banks. But, before we proceed to open branches of banks, we should train the staff. Our experience tells us that even after nationalisation, the managers and white-collared people do not have real involvement with the poorer sections of the society. I have seen and experienced it myself Unless we influence them, they will not give money. Therefore, special squads of officers have to be appointed to see that the money is reaching the people for whom it is meant. So, we are creating agencies and promoting corruption. Only real involvement of the people in their work can do away with all these evils.

We will give plans. We are happy the plans are there. But the plans must be backed by performance. Without performance, they will be of no use.

In order to combat inflation we have to boost production in both agriculture and industry. In this

country, unfortunately, whether it is the samall scale industry of agriculture, it is squeezed by the middle class, which is always flourishing. Even in the industrial sector there is no arrangement for proper marketing. It is only when there is proper marketing that there will be a proper price. Then the economic condition will automatically grow. So, we have to think seriously of the marketing facilities.

In Japan, when Hiroshima and Nagasaki were blasted, they were reduced to ashes. But now they are flooding every part of the globe with their products. One big American magnate said : Japan could not beat in war, but now they are in a position to purchase us. This is the state of affaris in Japan, because they work hard, for 14 to 15 hours a day. We have also to develop the morals and qualities of hard work by labour. Therefore, I would request the Government to see that lock-outs and strikes are banned and discipline is brought in. Otherwise, we will not be able to produce more and without increased production, inflation will eat us.

So far as inflation is concerned, our friends on the opposite side criticize us just for the sake of criticism. We welcome constructive criticism, but not just cynical criticism. They are very cynical. I would request them, though they are only two in number, to be constructive.

SHRI R. B. RAKESH : That also you do not like.

SHRI S. B. SIDNAL : If there is any constructive suggestion, we welcome it whole-heartedly. But, do not be cynical. Only two of you are present. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Only Shri Sidnal's speech will go on record. (*Interruptions*)**

SHRI S. B. SIDNAL : Another point that I would like to highlight is, in the coming ten years there will be scarcity of food. Therefore, afforestation must be taken up very much seriously. More gobar gas plants should be installed and subsidy for them increased. That will save us electricity. It could be used as fuel as also manure. It will help us to produce more manure and it will also be a substitute for electricity. It will be of great help to the peasants and farmers. Unless we take the gobar gas plant more seriously, in the coming ten years we will be having darker days without any wood to burn or construct buildings. So, I would request the Government to have a ten-year plan for afforestation. Every State should earmark areas for reserved forests. The amount which we spend on this project will be a very good investment. If we do not do it, in the coming days there will be scarcity.

I do not know much about public sector, though I have read a lot about them. There is much talk about corruption and favouritism. As Harold Laski and Dicey have said, these things are inevitable in a democracy. These evils exist along with democracy. Nobody can root out these things, but they can be reduced. The leakage in the public sector should be managed immediately taking any kind of action, and any type of discipline should be introduced immediately. Otherwise things will be very difficult for us in the coming days.

Lastly, much has been talked about the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes. We are claiming as the cream of the country, but we do not get involved with the development of our brothers. We have carried a bad tradition of loving dogs and cats but not human beings and now we are used to it. But we have to enlighten our society. When the Scheduled Castes, Schedulede Tribes

**Not recorded.

[Shri S. B. Sidnal]

and backward classes people come up, the affluent class or the forward block should take voluntary interest to improve the condition of economy or education or whatever it may be in respect of these people. Mere laws will never improve this country or any other country in the world. Unless people take serious interest in them, they will not be able to come up. Here, nationality has to be highlighted because the nationality is above our morality and personality. There should not be prestige issue or clash between nationality and personality. Then only this big country can have future in the coming days.

In the northern countries where we cannot the see sun for more than 6 months, under the buildings they have to grow vegetables or any crops and feed the pigs, cut them and eat them. In our country, in the open air we can grow everything and the only thing is that we are not properly planning or people are lethargic or whatever it is.

Lastly, decentralisation of LIC has been done and I congratulate the Government and the Finance Minister for this. There are so many other things to be decentralised. I do not want to take much time as every one of my colleagues has taken, but still I request the Government to think seriously about afforestation, gabar gas plants agricultural training centres and allied professions of agriculture like sheep breeding, poultry farming, dairy farming, bee-keeping, piggery, sericulture etc. The village industries should be developed.

Lastly, Sir, I request the Government to stop all licences in big cities. We should have parallel cities, parallel taluka places to develop. Otherwise, if we give one more industry in big cities, we have to face the problems of water, electricity and so many other things. Let us go to villages and develop them. To develop them we have to go in for rail-road coordination. So, rail-road coordination must be ensured.

About my State, I do not want to thank the Finance Minister because the Hospet plant is not given and the rail connection has not been given. We have been deprived of so many good lines like Karwar-Hubli line and other lines in Karnataka which would change the face of North Karnataka economically, educationally and socially. So, I request the Government to committ something on the Hospet plant in which our people are interested and which will develop our State all along. Karnataka is the nursery bed of Indira Congress in South apart from Andhra Pradesh. I do not request for an extra favour, but what is due must be given to us, which has been neglected for the last so many years and we have been telling our people that since our beloved Prime Minister has laid the foundation, it will be given.

Lastly, I request the friends on the other side to help to build new India.

Thank you very mcuh for having afforded me an opportunity to speak.

श्री जयपाल सिंह कश्यप (ग्रांवला) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट के बारे में मुझे यह कहना है कि धरती के लोगों ने आसमान की कल्पना कर के बजट बनाया है जिसमें केवल उद्योगपतियों, मिल-मालिकों, बड़े-बड़े व्यापारियों और मध्यम वर्ग में भी कुछ ऐसे वर्ग के लोगों के जो कि बड़े वर्ग की सीमा में आते हैं, के हित की बात की गई है। इस देश के करोड़ों करोड़ों किसान, मजदूर और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं है। इन कम टैक्स की जो भी रिलीफ आपने दी है उसका महंगाई पर, जैसा कि मेरे साथियों

ने बताया, कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इस बजट में इस देश के करोड़ों, करोड़ों और गरीब वर्ग के लोगों के वास्ते कोई चीज नहीं है, जिससे कि उनका हित होने वाला हो। आप पूरे बजट को उठा कर देख लें, आप कहीं भी ऐसी चीज नहीं पायेंगे जिससे कि गरीब वर्ग के लोगों को कुछ राहत मिल सके। गरीबों को सस्ता न्याय मिल सके, सस्ती शिक्षा मिल सके, उनकी बेरोजगारी दूर हो सके, ऐसा इस बजट में कुछ भी नहीं है। कुछ लाख लोगों की बात सोच कर के करोड़ों लोगों के बारे में सोचना केवल कल्पनामात्र है। इस बजट की आप तारीफ करते हैं और इसलिए तारीफ करते हैं कि यह आपकी मजबूरी है। नहीं तो इस बजट में आम लोगों के लिए क्या है ?

मैं उस पर इस समय नहीं जाना चाहता लेकिन इतना कहना चाहता हूं, कि इस समय इस देश की कैसी हालत हो गई है उसको आप सोच लें, नहीं तो आपका राज खत्म हो जायेगा। आज फूलनदेवी मल्हा का राज है, डाकू मलखान सिंह का राज है और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। आज लड़कियों को उठा कर जेलों से ले जाया जा रहा है, बसों से ले जाया जा रहा है। डाकू लोग ले जा रहे हैं। लोग गांव गांव में मारे जा रहे हैं। एक तरफ रात को डाकुओं का डर होता है और दिन में पुलिस के डाकुओं का डर होता है। चारों तरफ गांव गांव और छोटे-छोटे कस्बों में अराजकता फैली हुई है, कानन और व्यवस्था बिगड़ गई है लोगों का जीवन दूभर हो गया है।

इसे हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर देखना होगा क्योंकि हमारे बजट का प्रभाव केवल रोजी-रोटी, कपड़े और मकान तक ही सीमित नहीं है, उसके साथ उसके जीवन-मरण का प्रश्न भी है, कानून और व्यवस्था का भी प्रश्न है। हमें उसके जीवन की सुरक्षा भी देनी है, उसके गांव को भी सुरक्षित रखना है। उसको बिजली, भोजन, चीनी, मिट्टी का तेल पहुंचे या न पहुंचे वे यह बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन रात में या दिन में किस वक्त डाकू आ जायेंगे, लूट करेंगे, बेइज्जत करेंगे, माता और बहिनों की अस्मत लूटेंगे और दूसरी तरफ आपकी पुलिस ने भी वही काम करना शुरू कर दिया है, वह भी आपके हाथ से निकल गई है, वह भी डाकुओं से साजिश करती है, यह बात कैसे बर्दाश्त की जायेगी ?

पिछले दिनों की घटनाएं आप उठा कर देखिए कि किस तरह से हमारे बड़े बड़े शक्तिशाली लोग डाकुओं से मिले हुए थे और उनकी रक्षा करते थे और कहते थे कि इस गैंग को मार देना, इस गैंग को मत मारना, इसका घिराव करना लेकिन उसे निकल जाने देना, लेकिन दूसरे गैंग को जाल में फांसने को कहते थे। अब तक जातिवाद ने राजनीति में ही प्रवेश किया था लेकिन आज जातिवाद डाकुओं तक में प्रवेश कर गया है। इस देश का क्या होगा, इसको बड़ी गंभीरता से हम को सोचना होगा।

आप बात कहते हैं कि देश में गरीबों के लिए आपने बजट बनाया है आप उनको रोजगार देने की बात सोच रहे हैं। इस देश के जो असली रहने वाले हैं, जो बैठ कर के चाक चलाते हैं, कुम्हार लोग आपके लिए वर्तन और कुल्हड़ तैयार करते हैं, पान लगाने वाला तम्बोली आप लोगों के लिए पान लगा कर देता है, नाई जो कि बाल बनाता है, जिसकी कि एक माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे, क्या कभी आपने उनकी समस्याओं के बारे में सोचा है? क्या आपने जो तेली तेल निकालता है, अपना कोल्हू और बैल चला कर, इस देश का लोहार और बढ़ई आपके खेत का सामान

[श्री जयपाल सिंह कश्यप]

बैलगाड़ी आदि बना कर देता है, आपके घरों में इस्तेमाल होने वाली चीजें बना कर देता है, उसके लिए इस बजट में क्या है ? उन करोड़ों करोड़ों गरीब लोगों के लिए इस बजट में कुछ नहीं है जो गांवों में पाये जाते हैं जिनका कि परसेन्टेज काफी अच्छा है । वे लोग आज भी उपेक्षित हैं । आपके बजट में सुनार, लोहार, माली, दर्जी, धनुक, मछुआरे, नाविक के लिए कुछ नहीं है । आप इस देश के करोड़ों लोगों की उपेक्षा करके यह बजट बनायेंगे तो वह हवाई बजट कहलायेगा, इसको देहात का बजट कैसे कहा जायेगा । आप बड़ी-बड़ी छूटें दे रहे हैं, कह रहे हैं कि खाद्य का उत्पादन बढ़ाएंगे । उत्तर-प्रदेश में 7 घन्टे किसानों को बिजली दी जा रही है, यह कहा जाता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि वहां पर सिर्फ साढ़े तीन घंटे ही बिजली मिल पाती है । किसान फावड़ा ले कर खेत में जाता है, थोड़ी देर इंजन चलता है और बिजली चली जाती है । इस प्रकार से वहां पर मुश्किल से ढ़ाई तीन घंटे बिजली मिल रही है । इसी प्रकार डीजल नहीं मिलता है, डीजल की लाइनें लगती हैं, लोगों की दुर्दशा हो रही है, इस ओर आप बड़ी गंभीरता से सोचिये । अगर किसान की फसल नष्ट होती है तो आपकी पूरी अर्थ-व्यवस्था इस पर निर्भर है । आपके बिजली मंत्री कहते हैं कि बिजली देने के आदेश दे दिए हैं, लेकिन आपके एक्जीक्यूटिव आफिसर कहते हैं कि हम बिजली नहीं देंगे । खंबे गड़ चुके हैं, कर्जा वसूल करना शुरू कर दिया है, लोगों की कुड़कियां हो रही हैं, लेकिन बिजली नहीं पहुंची रही है । कुड़की के वारंट आ रहे हैं । मैं उत्तर प्रदेश के अपने क्षेत्र जिला बदायूं, बरेली की बात कर रहा हूं । सैकड़ों ऐसे किसान हैं, जिनके यहां पर कनेक्शन नहीं पहुंचे हैं और कुड़की के वारंट भेजे जा रहे हैं । लेकिन दूसरी ओर जो बड़े-बड़े कारखाने वाले हैं, जो बिजली की चोरी भी करते हैं और लाखों के बिजली के बिल जिन के ऊपर बकाया हैं, उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती है । उनसे कोई पूछने वाला नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से कहा गया कि किसानों को खाद चाहिए । खाद के ट्रकों के ट्रक बदायूं जिले के लिए बुलवाए गए, लेकिन सब के सब जातिवाद के आधार पर बांट दिए गए । बड़े-बड़े किसानों को दे दिए गए, छोटे किसानों को कोई लाभ नहीं मिला । जातिवाद के आधार पर ट्रक अलाट किए गए । एक क्षेत्र में 30 ट्रक और दूसरे में 200 ट्रक अलाट किए गए । बहुत से ट्रकों को ब्लैक में बेच दिया गया । इस बारे में सैकड़ों किसानों ने शिकायतें भी कीं, इस बारे में आप वहां के जिलाधीश से पूछ सकते हैं, लेकिन उस ओर कोई कार्यवाही नहीं की गई । मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि यदि इस देश में खाद्य समस्या का समाधान करना है तो वाटर-क्राप्स की ओर ध्यान देना होगा । मछली, सिंघाड़ा, कमलगट्टा आदि उत्पादन और इनका उत्पादन करने वाले मल्लाह, मछियारों आदि के विकास की ओर ध्यान देना होगा, इन्हें अधिक से अधिक राहत देनी होगी । आपने इन्हें नौकरियों में स्थान नहीं दिया है । अभी वर्मा जी ने बड़े अच्छे तरीके से कहा है कि इन्हें आरक्षण मिलना चाहिए था । इनकी हालत अनुसूचित जाति के लोगों से भी ज्यादा बदतर है । न तो इन्हें अनुसूचित जाति में रखा गया है, न जनजाति में रखा गया है । बहुत सी ऐसी जातियां हैं, एक दलेरा जाति है, ये न तो अनुसूचित जाति, जनजाति में हैं, न अपर क्लास में हैं, इनका कहीं पता नहीं है । इस प्रकार से उसको कैसे उन्नति के अवसर मिल पाएंगे । ये

लोग बीच में अटके हुए हैं। हमारे देश में 60 प्रतिशत बैकवर्ड लोग हैं । मण्डल-कमीशन की रिपोर्ट तैयार है, आप उसे जल्दी से जल्दी छपवाइए और सदन में प्रस्तुत कीजिये । उसे जल्दी से लागू करवाइए , आपके बजट का 5 पैसा भी उस पर खर्च नहीं होगा । 60 प्रतिशत लोगों को रिजर्वेशन मिलने पर उन लोगों में एक विश्वास जागेगा । जो लोग हजारों साल से उपेक्षित रहे हैं, धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जिनका शोषण हुआ है, उनको अवश्य ही राहत मिलनी चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय, एक चीज़ और मैं राजनीति से उठ कर कहना चाहूंगा कि हम लोग चाहे पार्लियामेंट के मेंबर हों, असेंबली में हों या कौंसिल के मेंबर हों, नौकरशाही हमसे खेल खेलती है । यह नौकरशाही जनता से खेल खेलती है । यदि आपको जनता के प्रतिनिधियों का सम्मान रखना है तो इसके लिए जरूर कुछ करना पड़ेगा । आज हर जगह नौकरशाही हावी है । इसको दूर करने के लिए जन प्रतिनिधियों को कुछ सेंसर करने के अधिकार दिए जाएं, जिससे वह इन नौकरशाहों को काबू में रख सकें । उसे अधिकार होना चाहिए कि वह उनकी रिपोर्ट सरकार तक भेज सकें, जनता की परेशानियां जिला अधिकारियों को बता सके। एक रजिस्तर मेंटेन कर सकें जिसके अनुसार वह महीने-दो-महीने में एक बार जो एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी हैं, उनको राय दे सकें, उनके काम को सेंसर कर सके, यह अधिकार उनको होना चाहिए ।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस बजट में गरीबों के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं ।

*SHRI OSCAR FERNANDES (Udupi): Mr Deputy Speaker, Sir, let me first congratulate our hon. Prime Minister and the Finance Minister for the budget he has presented to the House. I shall be brief and only touch upon important issues.

Sir, a nation's foreign exchange position is an indication of its economic health: according to this criterion our position is not satisactory and unless something is done to improve it we would not be able to make any progress. Countries like Korea, Taiwan, Japan and West Germany have improved their export position in spite of the shortage of raw materials. We must follow their example and develop our industry so as to make it export oriented. The economy would not improve unless we do this. A high-powered committee should be appointed to go into the question of boosting exports.

Discipline is the stepping stone to progress and the Government should make military training compulsory to instil a sense of discipline among the youth. If that cannot be done joining the NCC should be made compulsory for all youth.

We have a long coast line, but we have not taken steps to develop and exploit the marine wealth which is ours for the taking. Foreign trawlers fish in our waters but our poor fishermen cannot go to the high seas for fishing, not being equipped with sea-going fishing boats or trawlers. Some provision should be made in the budget for providing trawlers to fishermen.

Steps should be taken to step erosion by the sea. Dykes should be constructed to stop it. The Central Government should also take an early decision on the Malpe fishing harbour project estimated

*Original speech was delivered in Kannada.

[Shri Oscar Fernandes]

to cost Rs. 2 crores which has been forwarded by the Karnataka Government. The Centre should give funds to the State Government to complete the project and after it is completed and the major harbour of Mangalore is finished, a rail links between these two harbours should be constructed.

Unfortunately, not a single railway line has been included in this year's budget for Karnataka. The Konkan area is the only missing link in so far as railway communication network in Karanataka is concerned and it should be provided. A new line in Tamil Nadu has been sanctioned but Karnataks has been ignored. The Mangalore-Mal pe line should be undertaken even if the work is completed in stages. It will help transport bauxite ore which is available in Bandur, if the pace is connected with the railway system. Bauxite ore is at present transported by road. Bandur should also be connected with Karwar.

Credit facilities provided by the banks do not reach the common man. On an earlier occasion, the hon. Minister had promised to appoint an advisory board for bank credit for the common man : I hope that the promise would be filfilled soon.

There should be a circle office of the State Bank in Karnataka; that would decentralise the working of the Bank and sanctioning of loans would be expedited. If the LIC is going to be split into five corporations for a smoother functioning, there is no reason why a gargantuan bank like the State Bank of India cannot have its regional offices in each state for the benefit of the rural people. Larger number of branches should be opened to mobilise deposits from the common people of the country.

I earnestly request the Government to sanction the Mangalore Steel Plant which has been hanging fire for some time; another aluminium plant should be sanctioned for Bindur where there are bauxite deposits in large quantities. Shorebased plants should also come up as the Karnataka Government have proposed.

Sir, the Food Corporation of India which is responsible for supplying wheat and rice are not doing their job properly : the quality of the cereals supplied is not satisfactory. There is a strange paradox in our country; we are thinking of sending a man into the space, but we cannot guarantee quality of cereals for the people. The FCI should supply clean and dust free wheat and rice. Proper storing and handling techniques should be developed.

The energy crisis is not the only problem that our country faces. Government should encourage people to find solutions to the myriads of problems. One way could be to institute a prize of rupees one lakh for those who are able to suggest viable solutions to problems. I am sure that scientists would come forward and do their best to solve the difficulties and problem that our cluntry faces. Provision should be made in the budget for such prizes.

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सब से पहले आप को ही धन्यवाद दूंगा कि आप ने मुझे कुछ अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I wanted that you should be here and hear the ruling Party's speaker.

SHRI A. K. ROY : You should thank me. I am the lone listener without any aspiration to speak.

MR. DEPUTY-SPEAKER : You will be here always—I know.

THE DEPUTY-MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI MAGANBHAI BAROT) : I am here because I cannot help

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : जहां तक बजट का सवाल है इस की भूरि-भूरि प्रशंसा सभी मित्रों ने की है, लेकिन अगर बजट को देखा जाय तो यह केवल एक अंक-गणित का मायाजाल है, इस को हम मृग-मरीचिका कह सकते हैं।

इस से 25 लाख लोगों के आय-कर की छूट होती है और कुछ लाख लोगों को फायदा हो सकता है, लेकिन करोड़ों-करोड़ों जन-मानस के लिये इस में कोई व्यवस्था नहीं है। यह केवल वही अंक गणित है जिसे मोटी किताब के रूप में अंकों के मायाजाल को इस तरह घुमाया गया है जो देखने में लगता है अनुरक्षण है या रख रखाव का रूप है। जिस तरह से अमरीका में आइजनहावर जब प्रेजीडेंट हुए थे तो लोगों ने कहा था कि विद-आउट प्रैजीडेंट भी अमरीका चल सकता है, इसलिए इस बजट के बगैर भी देश चल सकता है। यह कह सकते हैं कि यह ब्यूरोक्रेसी का बजट है, यह केवल वेतन-पाने वाले लोगों की सुविधा के लिये है, उसी प्रकार की व्यवस्थाएं इस में हैं। लेकिन जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, 70, 72 प्रतिशत लोग उन के लिये कोई खास बात इस मे नहीं है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Verma what is your solution to bring them up? Please speak about that. We will also be enlightened

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, सजैशन भी मैं दूंगा, अगर आप मुझे समय देंगे। लेकिन क्योंकि आप ज्यादा समय नहीं देंगे, इसलिये मैं उसी को ख्याल में रख कर सारी बातें कहना चाहता हूं।

यह बजट केवल उसी तरह का है जैसे भौंकते हुए कुत्ते को दो रोटी फेंक देते हैं। उस प्रकार की कुछ व्यवस्था तो इस में हुई है, लेकिन देश के विकास या आम जनता जो गरीबी की रेखा से नीचे है, उस के लिये इस में कुछ नहीं है।

उधर के बहुत लोग कह गए कि यह बहुत अच्छा बजट है लेकिन संसद जो देश की सर्वोच्च संस्था है, इस के एयरकंडीशन्ड वातावरण में बैठ कर उधर के लोग कह गये कि यह बहुत अच्छा है, यहां बैठ कर जब तक नजर उन की घूमती रहती है तो यह अच्छा लगता है, लेकिन घाटा पहले से डबल हो गया है। यह घाटे का बजट है और बाहर जाने से आम जनता हम लोगों के पीछे झाड़ू ले कर पड़ती है।

आज मंहगाई ने सुरसा की तरह अपना बदन बढ़ा दिया है और गरीब तबके के लोग हनुमान की तरह उस के मुंह में जा कर समा रहे हैं। इस तरह की स्थिति सारे देश में हो रही है। चीनी के बारे में यहां सब बोलते हैं कि जनता पार्टी के शासन में वह अदृश्य हो गई। जनता पार्टी का शासन तो 27 महीने चला लेकिन कांग्रेस (आई) का शासनकाल तो पिछले 30 वर्षों से चल रहा है, उस के शासन में ही यह हो रहा है। इन्होंने कहा कि समाजवाद का ढांचा बनायेंगे, कभी हरित क्रान्ति और कभी सफेद क्रान्ति की बात करते हैं और पता नहीं कौन कौन सी क्रान्ति की ये बात करते हैं, जापानी तरीके की बात करते हैं लेकिन इस के बावजूद भी देश का जो कायाकल्प होना चाहिये, वह नहीं हो पाया है।

राजनेताओं के चरित्र का भी बहुत ही ह्रास हुआ है। इस में हम सभी दोषी हैं, हो सकते हैं, लेकिन समाज के लिये कोई नहीं सोचता, समाजवाद की बात करते हैं, इंडीविजुअ-लिज्म फर्स्ट। वैस्टेड इन्टरेस्ट वाले लोगों की तरफ जो लगाव है, उस के खिलाफ नहीं जा रहे हैं। इसलिये हम जनता को समाज के एक स्तर पर स्वयं नहीं ला पाते हैं। वैस्टिड इन्ट्रेस्ट के लोग और सरकार के साथ चिपके हुए चमचे ही सब कुछ हज्म कर जाते हैं, जिस के कारण आज देश की अर्थ-व्यवस्था अस्त-व्यस्त है। कोई नहीं कह सकता है कि यह बजट जन-हितकारी है। इससे कुछ लाख

[श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा]

लोगों का हित भले ही होता हो, लेकिन वह देश के करोड़ों लोगों के लिए हितकर नहीं है।

20.00 hrs

जहां तक मूल्य-वृद्धि का सम्बन्ध है, जनता सरकार के समय चीनी का दाम 2.60 रुपये किलो था। जबकि आज वह 6.10 रुपये किलो है। चीनी दस पन्द्रह रुपये किलो भी बिक चुकी है। कड़ुए तेल का दाम सात आठ रुपए से ज्यादा नहीं था, लेकिन आज वह 18 से 20 रुपये तक है। लोहे, कोयले और सीमेंट का दाम दुगना हो गया है। हर चीज का दाम बढ़ा है। इस सदन में इस ताप-नियंत्रित स्थान में—तो यह कहना ठीक लगता है कि यह बजट बहुत अच्छा है, लेकिन बाहर लोग गाली देते हैं। यदि सरकार अच्छा काम करे, तो विरोधी दल खत्म हो सकते हैं। लेकिन अगर सरकार अच्छा काम नहीं करेगी, तो परिणाम उसी को भुगतना पड़ेगा। जिस दल का शासन केवल दो वर्ष तक रहा, उस को सब गड़बड़ियों का दोषी या बलिदान का बकरा नहीं बनाया जा सकता है।

प्राइस को नियंत्रित करने के लिए सरकार हर स्टेट में प्राइस नियंत्रण बोर्ड बनाए, जिस में किसानों, उपभोक्ताओं और उद्योगों के दो दो प्रतिनिधि, आंकड़ों के विशेषज्ञों और सरकारी अधिकारियों के प्रतिनिधि रखे जायें। यह काम केवल बड़े आई ए एस अफसरों के सुपुर्द करने से कोई लाभ नहीं होगा, जिन को गांवों की स्थिति का पता नहीं है, जिन को मालूम नहीं है कि किसानों के सामने कितनी कठिनाइयां हैं और उत्पादकों, कारीगरों और निचले स्तर के लोगों को कितना परिश्रम करना पड़ता है।

आज सारे देश में बिजली की भयंकर कमी है। मेरा सुझाव है कि हर स्टेट में इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड का डेमोक्रेटाइजेशन कर दिया जाये। किसानों, उद्योगपतियों, उपभोक्ताओं, कर्मचारियों और इंजीनियरों के प्रतिनिधियों और जन-प्रतिनिधियों को उसमें रखा जाये। वे लोग सारी स्थिति पर नजर रखें और समय समय पर दोषों को दूर करने के लिए कदम उठायें। आज यह काम ऐसे लोगों को दिया जाता है, जो पब्लिक स्कूलों में पढ़े होते हैं, जिन को आम जनता से मिलने का अवसर नहीं मिलता है, जिन का सम्पर्क केवल पांच दस परसेंट अंग्रेजी बोलने वाले लोगों के साथ रहता है और जो केवल अखबार और कागज पढ़ कर ही अपना अभिमत बनाते हैं। इस तरह समूचे समाज का कायाकल्प नहीं हो सकता है।

अगर सरकार सब लोगों को काम देना चाहती है और सारी जनता की तरक्की करना चाहती है, तो देश का औद्योगीकरण उस का पहला काम होना चाहिए आज इंडस्ट्रीज बड़े-बड़े शहरों में सीमित है, जिस के कारण गांव अविकसित हैं और पिछड़े क्षेत्र पिछड़े हुए रह जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हर संसदीय क्षेत्र में कम से कम दो कारखाने लगाये जायें। इस से उस देश का काया-कल्प होगा, वहां के लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, उन्हें नई तकनीकी का ज्ञान होगा, नियोजन को नये आयाम मिलेंगे और साथ ही क्षेत्रीय असमानता, रिजनल इमबैलेंस खत्म होगा।

इसके साथ ही उद्योगों का श्रमीकरण भी होना चाहिए। हमारे देश में सार्वजनिक उपक्रम हैं और निजी क्षेत्र के उपक्रम भी हैं, मगर सार्वजनिक क्षेत्र सरकारी क्षेत्र के सब उपक्रम घाटे में चल रहे हैं। केवल प्राइवेट सैक्टर के लाभ में चल रहे हैं इसलिये कि उस के नियोजक और श्रमिक दोनों के बीच में एक तारतम्य सम्बन्ध किसी न किसी तरह बना रहता है। जहां तक

पब्लिक सैक्टर की बात है उस के अन्दर सरकार और कर्मचारी किसीको उसके प्रति श्रद्धा और प्रेम नहीं रहता । इसलिए जरूरी है कि मजदूरों को पब्लिक सैक्टर में, समाजवादी व्यवस्था के अन्दर जिस को पब्लिक सैक्टर कहा जाता है, उस में उन को एक हिस्सा दिया जाये, उन को प्रबन्ध और व्यवस्था में सहभागी बनाया जाय । जब फैक्ट्री घाटे में चलेगी तो मजदूरों को घाटा भुगतना पड़ेगा क्योंकि उस की हिस्सेदारी हो जायगी । उस के पसीने का मूल्यांकन हो, पूंजी का मूल्यांकन हो, लाखों श्रमिकों के बल पर यह देश चल रहा है । मैं कहता हूं कि जब तक ये लाखों श्रमिक लोग खड़े हैं तब तक देश खड़ा है । अगर यह श्रमिक गिर जायगा तो देश खड़ा नहीं रह सकता क्योंकि इन्हीं के बल पर ये नई नई बिल्डिंगें, रोड्स, बड़ी बड़ी नहरें और कारखाने बन रहे हैं । इसलिए श्रमिकों के श्रम को प्रतिष्ठा करनी होगी । डिगनिटी आफ लेबर को नजरअन्दाज नहीं कर सकते । आज 25 लाख लोग पब्लिक सैक्टर के हड़ताल पर बैठे हैं । सरकार ने कानून बनाए हैं । मेरा यह कहना है कि जितना मूल्य बढ़ता है, मूल्य सूचकांक के साथ वेतनमान को जोड़ देना चाहिए । अगर मूल्य-सूचकांक के साथ वेतनमान नहीं बढ़ता तो निश्चित रूप से हड़ताल होगी, सौदेबाजी होगी, नाना प्रकार की कार्यवाही श्रमिक लोग करेंगे । इसलिए मेरा सुझाव है कि उन लोगों को सहभागी बनाया जाय, उद्योगों का अभिकिकरण किया जाय तो यह देश के लिए कल्याण-कारी हो सकता है । जब देश के निर्माण के कार्यों में लाखों करोड़ों मजदूर लगे हुए हैं तो श्रमिकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए ।

अब एक बात मैं अपने क्षेत्र की कहना चाहता हूं । रेल-उप मंत्री श्री मल्लिकार्जुन जी बैठे हुए हैं, इन्हीं का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूंगा । हमारा क्षेत्र बिहार का सब से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । वहां चार जिले पड़ते हैं जहां कि एक रेल लाइन के लिए वर्षों से लोग मांग कर रहे हैं—गिरिडीह, हजारीबाग, रांची और संथाल परगना । यह सब लोग जानते हैं कि वहां कोयला, लोहा, अभ्रक और नाना प्रकार के खनिज, कितने ही तरह के द्रव्य और ठोस पदार्थ उपलब्ध हैं जिस के लिए ठोस यातायात की व्यवस्था वहां होनी चाहिए थी, लेकिन आज तक नहीं हो सकी । उस क्षेत्र की जनता ने बार बार कहा । अभी हाल ही में बजट में हम ने देखा, उस में बराबर रूट चेंज करते रहते हैं । लगता है कि ब्यूरोक्रेसी का एक ऐसा ढंग है कि कभी इधर सर्वेक्षण करा दो, कभी वैकल्पिक करो, इस तरह से करते करते 33 वर्ष गुजर गए । तो उस में गिरिडीह से कोडरमा, कोडरमा से हजारी बाग टाउन, हजारीबाग से रांची, यह 220 किलोमीटर का एक रेल पथ होगा जिस में 30 स्टेशन बनेंगे, 30 नये नगर बनेंगे, तीसों में लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और इस में बहुत वैकल्पिक लाभ होगा । हमारे रेल उप मंत्री ने एक पत्र हमें दिया था और हमारे निवर्तमान रेल मंत्री त्रिपाठी जी ने भी मुझे पत्र दिया था । अभी जैसा कि बजट में जोड़ दिए थे, गिरीडीह से हजारीबाग रोड, हजारीबाग रोड से हजारीबाग और हजारीबाग से रांची, इन सब की वैकल्पिक जांच कर रहे हैं । वह केवल जनरल में है और उस में 12 लाख रुपए का सर्वेक्षण का कार्यक्रम बजट में जोड़े हैं । यह कितने अपव्यय की बात है क्योंकि 75-76 में उस का सर्वेक्षण हो चुका है और वह मुझे बता चुके हैं, मंत्री जी के पत्र का नम्बर भी मेरे पास है — उस में 1975 में उन्होंने बता दिया कि एकोनामिकली वायबल नहीं है । इसीलिए बिहार सरकार के वर्तमान मुख्य मंत्री जगन्नाथ मिश्र और भूतपूर्व मुख्य मंत्री कर्पुरी ठाकुर, दोनों मुख्य मंत्रियों ने रेकमेंड किया कि उस का वैकल्पिक जो है गिरीडीह-जमुवार, धनवार और कोडरमा होते हुए इस रेलवे लाइन को बनाया जाय ताकि इस देश का विकास हो सके । इसलिए इस तरह का सुधार करना चाहिए । हमारे रेल मंत्री केदार पांडे जी ने भी कहा कि छोटा नागपुर

[श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा]

में भी एक रेलवे लाइन बनानी है। . . . (व्यवधान) . . . .

बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर जो भोजपुर और बलिया, इन जिलों के बीच में पांच लाख किसान रहते हैं उन में कौरव-पाण्डव की लड़ाई हो रही है। गंगा और घाघरा नदी की धारा बदलते रहने से 50 मील लम्बा और 10 मील चौड़ा यह एक बलुहाई क्षेत्र है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Your party has exhausted the time. I have given you time as a special case. Please conclude.

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : मैं समाप्त कर रहा हूं।

दो फरवरी से बक्सर के एस डी ओ के यहां किसान भूख-हड़ताल कर रहे हैं, 100 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। और 500 लोग 107 के अन्तर्गत आ चुके हैं। उन किसानों की एक ही मांग है कि बिहार, उत्तर प्रदेश सीमा परिवर्तन अधिनियम 1968 की धारा 32 के अनुसार जो बिहार सरकार ने 144 गांवों के नाम उत्तर प्रदेश को दिए और भू-अभिलेख के कागजात दिए उस के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार को तुरन्त ही मान्यता दे कर मालगुजारी रसीद इश्यु कर देनी चाहिए, ताकि कोई झंझट न हो।

इस समय गेहूं की फसल लगी हुई है, वहां पर गोली-बारी सब कुछ होता है, भयंकर लड़ाई उन में चलती है, इस की ओर सरकार और गृह मंत्री को ध्यान देना चाहिए और वहां पर फसल काटने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए।

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं इस झगड़े में जाना नहीं चाहता हूं, जैसा कि हमारे अपोजीशन के भाइयों ने कहा कि यह बजट जो है वह आम लोगों के लिए नहीं है। हकीकत जो है वह आपके सामने है। यह जो बजट पेश किया गया है, मैं समझता हूं बेहतरीन बजट है। गरीबों के लिए और खुसूसी तौर पर ट्राइबल, शेड्यूल्ड कास्ट्स और जो वीकर-सेक्शन्स हैं उन के लिए यह बजट एक अहमियत रखता है। यह बजट, इन्दिरा जी के पावर में आने के बाद, जो उन्होंने अपने लोगों के साथ वायदा किया था, उसको पूरा करने की तरफ पहला कदम है। मैं पहला कदम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले जो बजट पेश किया गया था वह तो, जनता पार्टी के जमाने में जिस घर को बिगाड़ बैठे थे या उस पिलर्स को हिला बैठे थे उसको दोबारा ठीक करने के लिए था और यह बजट पहला इस सेन्स में कि जो इन्दिरा जी ने एलेक्टोरेट के साथ वायदा किया था उसको पूरा करने की तरफ एक अहम स्टेप है।

मैं फीगर्स में जाना नहीं चाहता हूं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जो 17,478 करोड़ की रकम आपने सेक्टर, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए मखसूस की है उसमें से सेण्टर के लिए 8,619 करोड़ है और बाकी 8,807 करोड़ स्टेट्स के लिए रखा है, एक बहुत बड़ी रकम है।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से गुजारिश करूंगा, वैसे आपने स्टेट्स और सेण्टर के लिए काफी रकम और प्रोग्राम रखा है, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको ज्यादा ध्यान देना होगा। खास करके जो फिजिकल एचीवमेंट हैं, उनको पूरा करने की जरूरत है। महज पैसा देना ही काफी नहीं होता है, उनके इम्प्लीमेंटेशन की ओर आपको ज्यादा ध्यान देना होगा।

खास करके उन स्टेट्स के लिए जहां कांग्रेस (आई) की हुकूमत नहीं है, मिसाल के तौर पर वैस्ट बंगाल है, तमिलनाडु है, केरल है और जम्मू-काश्मीर है—इन स्टेट्स की जो हुकुमत हैं, वे सैण्टर पर तरह-तरह के दबाव डालकर और तरह-तरह की ब्लैक-मेलिंग करके यह कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा रकम वसूल की जाए और वह भी उन स्टेट्स की कॉस्ट पर जहां कांग्रेस (आई) की हुकूमत है। तो देखना यह है कि उन में से किस हद तक फिजिकल एचीवमेंट की तरफ यह रकम खर्च की जा रही है। जहां तक मेरी स्टेट का तालुक है, मुझे इल्म है कि वहां पर जो फण्ड्स सैण्टर से हासिल किया जा रहा है, वह नान-प्रोडक्टिव स्कीम पर डाइवर्ट किया जा रहा है। नान-प्रोडक्टिव स्कीम पर इसलिए डाइवर्ट किया जा रहा है कि उस में ज्यादा करप्शन के चांसेस हैं और उसमें गुंजाइश होती है। मिसाल के तौर पर जैसे बिजली है, प्रोडक्शन साइड पर है, एग्रीकल्चर है या दूसरी-तीसरी ऐसी स्कीमें हैं, जिन पर खर्च नहीं हो पा रहा है। लेकिन उसको लगा रहे हैं मकान बनाने पर, अफसरों के लिए बंगला बनाने में—ऐसे कामों पर खर्च होता है, जिसमें ज्यादातर करप्शन होता है और अफसरों तथा मिनिस्टरों की जेब में चले जाते हैं। इसके लिए आपको देखना है कि इसको कैसे चैक किया जाए।

मेरी तजवीज यह है कि आपको एक एजेंसी कायम करनी चाहिए जिससे कि हर स्टेट में यह देखा जा सके कि वाकई जिस मकसद के लिए, जिस स्कीम के लिए आपने पैसा सैन्क्शन किया है, वह उसी मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है या नहीं।

दूसरा सजैशन मेरा यह है कि किसी को भी एक हैड से दूसरे हैड में एप्रोप्रिएट करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, इसके लिए आपको स्ट्रीकटली इन्स्ट्रक्शन देनी चाहिऐ, खास करके नान-प्रोडक्टिव स्कीम की तरफ एप्रोप्रीएट करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए, जिसको खास तौर पर करप्शन करने के लिए डाईवर्ट किया जा रहा है।

तीसरी बात यह है कि खास करके जो नौन-कांग्रेस (आई) स्टेट्स हैं, वहां पर ओवर-ड्राफ्ट भी ज्यादा हो रहा है। इस लिए मेरा सुझाव है कि यदि कोई सरकार चाहे कांग्रेस (आई) हो या नौन-कांग्रेसी हो ओवर-ड्राफ्ट करता है, तो स्ट्रीकटली उनके नैक्स्ट इयरस बजट में से किसी कन्सैशन के बगैर उस राशि को आपको डिडक्ट करना चाहिए। इससे यह जो आपका 1800 करोड़ रु० का घाटा है, डैफिसिट है, उसको पूरा किया जा सकता है।

अब मैं आपका ध्यान सिविल-एविएशन-डिपार्टमेंट की तरफ ले जाना चाहता हूं। आपको पता ही है कि हमारे इलाके पिछड़े हैं और जहां पर साल में सात महीने सड़क बन्द रहती है। जिस की वजह से हमारे यहां हवाई जहाज के बगैर आने-जाने का और कोई साधन नहीं है। चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो; दूसरी दुनिया के साथ हवाई जहाज के अलावा और कोई लिंक नहीं है। वैसे हम आप के बहुत मशकूर हैं—आपने जनवरी, 1979 में हमारे यहां एअर-सर्विस शुरू कर दी थी, लेकिन उस के किराये इतने ज्यादा हैं जो हमारे लोगों के बरदाश्त के बाहर है। यह ठीक है कि आप ने रिटर्न-टिकट का कन्सेशन दिया है, लेकिन उस में आप ने कुछ ऐसी टाइम-लिमिट रख दी है कि तीन दिन के अन्दर अगर कोई वापस आता हो तो वह उस कन्सेशन को अवेल नहीं कर सकता है—यह नहीं होना चाहिए।

[श्री पी० नामग्याल]

दूसरी बात—जनवरी, 1979 में जब आप ने एअर-सर्विस शुरू की, उस वक्त फ्यूअल के प्राइस काफ़ी बढ़ चुके थे, आप ने उस वक्त जो किराया तय किया, उसमें 1979 की आयल-प्राइस और 50 परसेण्ट आक्यूपैन्सी को मद्देनजर रख कर किया था। उस वक्त यह कहा गया था कि 50 परसेण्ट से ज्यादा पैसेन्जर्स नहीं आयेंगे, साथ ही हाई-आल्टीचूड पर पूरी लोड-कैपेसिटी नहीं ले जा सकते। इस लिए उस किराए को हायर-साइड में रखा गया था, लेकिन आप के दूसरे रूट्स पर जो किराये थे वे वही थे जो 1974 में फिक्स किये गये थे, तेल में दाम बढ़ने के साथ-साथ उन को नहीं बढ़ाया गया था। उस के बाद मई, 1979 में आप ने आल-ओवर-इण्डिया 35 परसेण्ट किराया बढ़ाया, चूंकि आप ने 1974 से किरायों को रिवाइज नहीं किया था। इस के आधार पर आप ने हमारे रूट पर किराये को भी 35 प्रतिशत बढ़ा दिया, हालांकि उस को पहले ही बढ़ा कर रखा गया था और 35 प्रतिशत बढ़ाने का कोई ज्वाजीयत नहीं रखते थे। उस के बाद फिर तीसरी बार फ्यूअल-सरचार्ज 25 परसेण्ट बढ़ा कर आप ने किरायों को रिवाइज किया, चौथी बार फिर आप ने 5 परसेण्ट सरचार्ज लगाया—इन सब का नतीजा यह हो रहा है कि हम को दूसरे रूट्स के मुकाबले डबल किराया देना पड़ रहा है। जो रिटर्न-फेअर कन्सेशन आप दे रहे हैं, वह भी इस वक्त सही कैलकुलेशन की जाये तो हायर-साइड पर है। आक्यूपैन्सी रेशो का जहां तक सवाल है कि जहाज में जगह नहीं मिलती है। हमारा यह खास मसला है जिस की तरफ ध्यान देने की जरूरत है।

एक दूसरा मसला यह है कि श्रीनगर से लेह के दरमियान 30 मिनट की फ्लाइट है, जो दिल्ली से चण्डीगढ़ के लिए भी है, लेकिन दिल्ली से चण्डीगढ़ की 30 मिनट की फ्लाइट का किराया 188 रुपये है जब कि श्रीनगर से लेह की 30 मिनट की फ्लाइट का किराया 358 रुपये हैं — इस से आप अन्दाजा लगा सकते हैं . . .

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please conclude now. You can speak about this during the discussion on Demands for Grants for Civil Aviation. In any case, the Finance Minister is not going to reply to this point. You can speak on the Appropriation Bill also.

श्री पी० नामग्याल : मैंने आप से यही अर्ज किया है प्राडक्टिव से नान-प्राडक्टिव स्कीम्ज में रीं-एप्रोप्रियेशन नहीं होना चाहिए, दूसरे बैंकों से जो ओवर-ड्राफ्ट ले लिया जाता है उस पर रोक लगाई जानी चाहिए, ताकि बजट डेफिसिट का जो गैप है वह किसी हद तक पूरा किया जा सके, तीसरी बात मैंने लेह की एअर-सर्विस के बारे में अर्ज करदी है—इन बातों पर गौर किया जाना चाहिए।

आखिर में यही अर्ज करना चाहता हूं कि आप ने जो बजट पेश किया है यह

खास तौर पर गरीबों के लिए है, उसके बाद मिडिल-क्लास के लिए है और हमारे मुल्क की ओवर-आल इकानामिक कण्डीशन के लिए, मैं समझता हूं, इस से अच्छा बजट नहीं आ सकता था। ओवरआल हमारे मुल्क की एकोनोमिक कंडिशन्स के लिए, मैं समझता हूं, इस से अच्छा और कोई बजट नहीं हो सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

20.26 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, March 13, 1981/*Phalguna* 22, 1902 (*Saka*).

GMGIPND—M—4198 L. S.—14-5-81—890